भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

सकारात्मक साप्ताहिक हिन्दी अखबार

जागरूक जनता

4 फरवरी- 10 फरवरी 2026

jagrukjanta.net

माघ, पक्ष - कृष्ण, तिथि - तृतीया, संवत 2082 पृष्ठ : 8 जयपुर, बुधवार वर्ष-11, अंक-49, मूल्य ₹ 5/- वार्षिक मूल्य : ₹ 250/-

सीतारमण का रेकॉर्ड

निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। ये अपने आप में रेकॉर्ड है। पहला बजट 2019 में पेश किया था। तब स्पीच 2 घंटे 8 मिनट की थी। ये भी एक रेकॉर्ड था।

जेनरेशन चेंज बजट

देश को नेक्सट लेवल पर ले जाने का वादा

वो वक्त बदल रहा है, जो बजट का मतलब इनकम टैक्स में बदलाव भर मानता है। सोशल मीडिया पर नई पीढ़ी को समझने की कोशिश करिए। उसे चाहिए, भारत की फ्यूचर प्लानिंग। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी समझती है कि पुराने फॉर्म्यूले नहीं चलेंगे। इस बार उनके बही खाते में जेनरेशन चेंज दिखा, जो भारत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वादा करता है। नई पीढ़ी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। उसके लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बेहतर जिंदगी की उसकी चाहतों को पूरा करना ही होगा। तभी वित्त मंत्री ने भाषण की शुरूआत में ही इस बात को साफ कर दिया, यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है।

ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवाशक्ति और नारीशक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है।
-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

राहुल बोले- संकट पर आंखें बंद वित्त मंत्री ने कहा- फैक्ट दें

बजट पर हॉट डिबेट

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि बजट समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है। सीतारमण ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे (राहुल गांधी) किन चीजों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और उसकी बुनियाद मजबूत है। वैश्विक अनिश्चितता हमारे कई सेक्टर्स प्रभावित कर रही है, जिनके लिए हमने लघु-मध्यम उद्यमों, कपड़ा और चमड़ा उद्योग... किसानों और महिला उद्यमियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर लिखा, ये ऐसा बजट है, जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई है। वित्त मंत्री ने कहा, हम आम छोटे लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बाहर से आने वाली किसी भी वोलैटिलिटी से जिंदगी में बड़े बदलावों का सामना न करना पड़े।

राहुल गांधी के सवाल पर वित्त मंत्री का पलटवार

युवाओं के पास जॉब नहीं है, मैन्यूफैक्चरिंग गिर रही, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत घट रही, किसान संकट में। इकॉनमी को वैश्विक झटका लगा, उसे अनदेखा किया गया। -राहुल गांधी

पॉलिटिकली आप बुराई करना चाहते है, प्लीज करें। अगर आप वे फैक्ट्स देना चाहते है जिन पर आप अपनी बात रख रहे है तो मै सुनने और जवाब देने को तैयार हूं। -निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट, दिखे कई रंग

निर्मला सीतारमण ने 31 मई 2019 को वित्त मंत्रालय संभाला। उनकी बजट स्पीच की लंबाई से लेकर साड़ी तक की भी हर बार चर्चा होती रही है। पिछले 8 बजट की ये तस्वीरें हैं।

पीएम मोदी बोले

'रिफॉर्म एक्सप्रेस में भारत, बनने जा रहा तीसरी बड़ी इकॉनमी'

बजट को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। इस बजट से यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुल गया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। बजट से भारत की ग्लोबल पोजिशन मजबूत होगी। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। ये विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते है। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुला: PM

वर्कफोर्स में Gen Z

देश में वर्कफोर्स का करीब 25% हिस्सा Gen Z का, साल 2030 तक 36% होने का अनुमान।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

UNION BUDGET 2026-27

38 करोड़ है आबादी

1997-2012 के बीच जन्म लेने वालों को Gen Z कहा जाता है। आबादी करीब 38 करोड़ है।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

सवाल-जवाब से जानें, क्या-क्या बदल जाएगा

नन्द किशोर वर्मा, वरिष्ठ लेखाकार

टैक्स स्लैब में भले ही राहत न दी गई हो लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में कई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिनसे आम आदमी को आसानी होगी और उसका फायदा होगा।

रिटर्न फाइल करने के प्रॉसेस को कैसे आसान बनाया?

सरकार ने टैक्स रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए है। रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त तीन महीनों का लाभ लेने पर फीस देनी होगी- पांच लाख से अधिक आय पर 5,000 रुपये और पांच लाख या उससे कम आय पर 1,000 रुपये। नॉन-ऑडिट केस, जैसे छोटे बिजनेस और ट्रस्ट के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है, जबकि सैलरीड वर्ग के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 की तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।

विदेश टूर पैकेज पर टैक्स कितना कम?

विदेशी यात्रा के टूर पैकेज पर TCS (Tax Collected at Source) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों पर खर्चा कम होगा। पहले विदेशी टूर पैकेज पर 10 लाख रुपये तक 5% TCS और 10 लाख से अधिक पर 20% TCS लगता था। अब सरकार ने इसे सिर्फ 2% TCS कर दिया है, चाहे पैकेज की कीमत कितनी भी हो। 10 लाख रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट भी हटा दी गई है। यानी अब सभी विदेशी टूर पैकेज पर केवल 2% TCS ही लागू होगा। जमा किया गया TCS रिफंडेबल है और आईटीआर फाइल करते समय रिफंड लिया जा सकता है।

विदेश पैसा भेजने पर कितना टैक्स लगेगा?

पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसा भेजने पर अब कम टैक्स लगेगा। अभी जब कोई व्यक्ति पढ़ाई या इलाज के लिए फॉरेन रेमिटेंस करता था तो उस पर 5% टीसीएस लगता था। शिक्षा और मेडिकल के अलावा किसी और काम के लिए पैसा भेजने पर 20% टीसीएस अप्लाई होता है। सरकार ने शिक्षा और मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए टीसीएस रेट को 2% करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा किसी और मकसद के लिए टीसीएस 20% ही रहेगा। अगर पैसा एजुकेशन के लिए लोन के जरिए भेजा जा रहा है तो इस पर टीसीएस रेट अब भी 0.5% ही रहेगा जैसा पहले था।

फॉरेन असेट घोषित करने के लिए क्या स्कीम आई है?

सरकार ने टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 पेश की है। इसका उद्देश्य उन ईमानदार टैक्सपेयर्स को मौका देना है जिनके पास सीमित मूल्य की विदेश संपत्ति या आय है और जो रिपोर्टिंग में चूक गए। इस स्कीम में 31 मार्च 2026 को एक करोड़ रुपये तक की वैल्यू वाली फॉरेन असेट या इनकम शामिल होगी। अगर असेट का स्रोत साफ है लेकिन रिपोर्ट मिस हुई है, तो लिमिट पांच करोड़ रुपये तक होगी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करने पर 30% टैक्स और 30% अतिरिक्त देना होगा, यानी कुल 60%।

ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा पर क्या नियम बदले?

सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा करने पर लगने वाले जुर्माने के नियमों में बदलाव किया है। पहले अधिकतम पेनल्टी 1,50,000 रुपये तक थी, जिसे अब घटाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, यदि ऑडिट रिपोर्ट देरी से लेकिन एक महीने के भीतर जमा कर दी जाती है, तो 75,000 रुपये शुल्क देना होगा। एक महीने के बाद जमा करने पर 1,50,000 रुपये का शुल्क लागू रहेगा। इस राशि को अब 'पेनल्टी' की जगह 'फीस' माना जाएगा, जिससे कारोबारी इसे खर्च के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती का लाभ ले सकेंगे।

कोऑपरेटिव सोसायटी, मेंबर्स के लिए क्या फायदा?

सहकारी समितियां भी कंपनियों या अन्य सहकारी समितियों में निवेश कर डिविडेंड प्राप्त करती हैं। मौजूदा नियमों में कंपनी से मिला डिविडेंड संबंधित सहकारी समिति के हाथ में टैक्सेबल माना जाता है, जबकि दूसरी सहकारी समिति से मिला डिविडेंड विशेष कटौती के लिए पात्र होता है। अब तक यह कटौती केवल ओल्ड टैक्स रेजीम चुनने वाली समितियों को मिलती थी। प्रस्ताव है कि यह लाभ न्यू टैक्स रेजीम में भी मिलेगा, बशर्ते प्राप्त डिविडेंड आगे सदस्यों में वितरित किया जाए। यह बदलाव समितियों और उनके सदस्यों, दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

टीडीएस को लेकर कौन से बदलाव हुए हैं?

इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 के तहत कम या निल टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अब प्रक्रिया आसान होगी। पहले टैक्सपेयर को असेसिंग अफसर के पास आवेदन देना पड़ता था, जो संतुष्टि पर सर्टिफिकेट जारी करता था। अब आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा और प्राधिकरण डिजिटल जांच कर निर्णय लेगा। पात्रता और प्राधिकरण को सीबीडीटी नोटिफाई करेगी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद में भी राहत है। नॉन-रेजिडेंट विक्रेता के मामलों में टीडीएस के लिए TAN की अनिवार्यता हटेगी। अब खरीदार केवल PAN के आधार पर टीडीएस काट सकेगा।

कारोबार आसान बनाने और मुकदमेबाज़ी कम करने पर वित्त मंत्री का फोकस

इनकम टैक्स स्लैब जस का तस, नया ऐक्ट 1 अप्रैल से ही, नियम-फॉर्म जल्द

जागरूक जनता jagrukjanta.net

एक्सपर्ट व्यू

जी.एस. धामाणी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

नए इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 का उद्देश्य नियम सरल बनाना है। आयकर स्लैब वही रहेंगे, कोई नई छूट नहीं। कानून में सुधार, पेनल्टी सरल, शेयर और TCS नियम बदलकर कारोबार आसान बनाने की कोशिश की गई है।

नया इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 एक अप्रैल से लागू होगा। अभी यह ऐक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है और नोटिफाई भी हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐक्ट तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक उससे जुड़े रूल्स-रेग्युलेशन और फॉर्म्स को भी जारी किया नहीं जाता। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह रूल्स और फॉर्म्स जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे और नए ऐक्ट के लागू होने की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां तक इसके लागू होने से पड़ने वाले फर्क की बात करें तो इससे इनकम टैक्स के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं आएगा।

नए ऐक्ट में सभी प्रावधानों को सलीके से पेश किया गया है। पहले यह कई सेक्शनों में अलग-अलग बिखरे हुए थे, अब एक बात को पूरी तरह से एक जगह पर ही कह दिया गया है। इससे सेक्शन कम हो गए। इसके अलावा भाषा को भी सरल किया गया है। ऐसा अनुमान है कि रूल्स और फॉर्म्स को भी आसान रखा जाएगा ताकि मुकदमेबाजी ना हो।

इस बार के बजट में सामान्य व्यक्ति (साधारण करदाता) को टैक्स छूट के रूप में कोई नई राहत नहीं दी गई है। आयकर के जो स्लैब पिछले वर्ष तक लागू थे, वही आगामी वर्ष में भी लागू रहेंगे। वास्तव में, किसी को अतिरिक्त छूट की विशेष उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पिछले वर्ष ही नए टैक्स रेजीम में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत थी। इसलिए इस वर्ष किसी और बड़ी राहत की अपेक्षा करना उचित नहीं माना जा सकता।

हालांकि, कई सुझाव और प्रयास किए जा रहे थे, जैसे- नए टैक्स रेजीम में हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट दी जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाई जाए, शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की बेसिक एग्जेम्शन लिमिट को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाए, पति और पत्नी की जॉइंट इनकम पर टैक्स लगाने से संबंधित प्रावधान लाए जाएं आदि। लेकिन इस बार के बजट में इनमें से कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया गया।

इस बजट का मुख्य उद्देश्य कोर्ट-कचहरी के मामलों को कम करना और कारोबार करना आसान बनाना है। सरकार कई नियमों को सरल बना रही है। छोटे-मोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माना बनाया जाएगा। कुछ पेनल्टी अब फीस की तरह ली जाएंगी। शेयर बाय-बैक के नियम बदले जाएंगे। TCS नियमों में राहत दी गई है, जबकि शेयर बाजार लेनदेन पर STT थोड़ा बढ़ाया गया है। इससे बिजनेस माहौल बेहतर करने की कोशिश है।

वहीं, बजट 2026 में क्रिप्टो एसेट लेनदेन की गलत या अधूरी रिपोर्टिंग पर सख्ती का प्रस्ताव है। एक्सचेंज, मार्केटप्लेस जैसे संस्थानों को तय विवरण देना होगा। स्टेटमेंट न देने पर 200 प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। गलत जानकारी देने और सुधार न करने पर 50,000 की पेनल्टी प्रस्तावित है। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और गैर-अनुपालन रोकना है।

AI Image

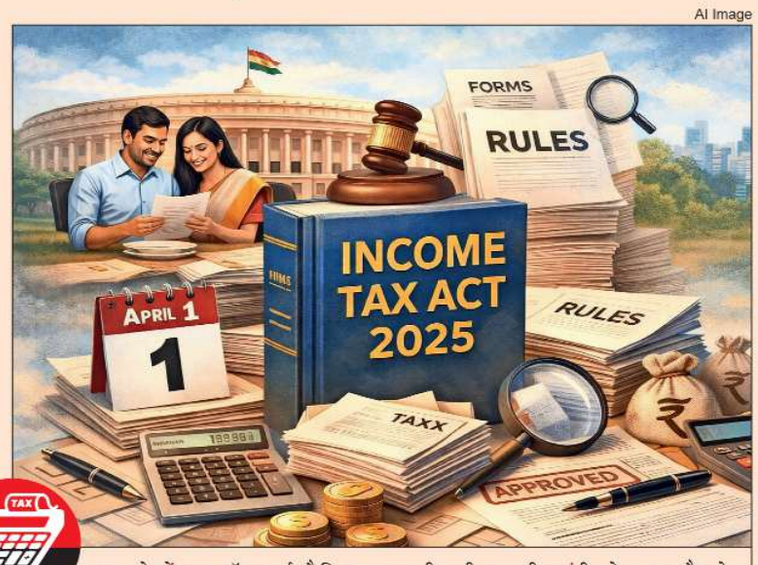

इस तरह होगी टैक्स की गणना

मौजूदा समय में इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ओल्ड और न्यू दो टैक्स रेजीम हैं। इनके स्लैब जस के तस रखे गए हैं। आप जिस भी रेजीम को फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से टैक्स की गणना अब भी पहले की तरह ही होती रहेगा। यहां पेश हैं दोनों रेजीम के टैक्स स्लैब।

न्यू टैक्स रेजीम

नया टैक्स स्लैब	टैक्स रेट
0-4 लाख रुपये	Nil
4-8 लाख रुपये*	5%
8-12 लाख रुपये*	10%
12-16 लाख रुपये	15%
16-20 लाख रुपये	20%
20-24 लाख रुपये	25%
24 लाख रुपये ऊपर	30%

*नोटः *न्यू टैक्स रेजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है।*

ओल्ड टैक्स रेजीम

टैक्स स्लैब	टैक्स रेट
2.5 लाख तक	Nil
2.5 से 5 लाख तक	5%
5 से 10 लाख तक	20%
10 लाख से अधिक	30%

4 टैक्स स्लैब, 30% तक टैक्स

SITUATIONSHIP सिचुएशनशिप

न कमिटमेंट और ना दूरी

सिचुएनशिप (Situationship) असल में एक अनौपचारिक रिश्ता होता है, ना पूरी तरह कमिटमेंट, ना पूरी तरह दूरी। यानी साथ भी हैं, लेकिन साफ नहीं कि किस हैसियत से। रिश्तों के संदर्भ में:

- बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जैसा व्यवहार, लेकिन कोई स्पष्ट स्टेटस नहीं
- भविष्य को लेकर अनिश्चितता, सुविधा है, पर जिम्मेदारी नहीं।
- फायदे हैं, लेकिन वादे नहीं।

Gen-Z की भाषा

इकॉनमी का 'बीच का खेल'

इकॉनमी में यह शब्द रूपक (metaphor) की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रोथ और मंदी के बीच की हालत यानी जब इकॉनमी मंदी में भी नहीं, तेज विकास में भी नहीं तो कहा जा सकता है: Economy is in a situationship with growth। इसका अर्थ संभावनाएं हैं, पर भरोसा नहीं। इकॉनमी में situationship का मतलब है ऐसी स्थिति जहां उम्मीद, अनिश्चितता साथ-साथ चल रही हो।

BENCHING बेंचिंग

खेल नहीं, रिश्तों की नई भाषा

बेंचिंग शब्द भी आजकल रिश्तों से लेकर इकॉनमी तक एक तेज और अर्थपूर्ण रूपक बन चुका है। चलिए इसे उसी अंदाज में समझते हैं।

*किसी को पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन प्राथमिकता भी नहीं। यानी **Backup option** बनाकर रखना*

- ना साथ, ना विदाई = Emotional benching

वैसे Benching की जड़ खेल (क्रिकेट/फुटबॉल) से है। खिलाड़ी टीम में है, मैदान पर नहीं और जरूरत पड़ने पर उतारा जा सकता है। यानी रिजर्व में रखना।

Skill है, Demand नहीं

*मिसाल के तौर पर स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध है लेकिन **demand** कमजोर है या टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन चल रहा है। यानी **Talent** है, लेकिन उपयोग नहीं = **Benched economy***

- इसी तरह कंपनियों के पास पैसा है, बैलेंस शीट मजबूत है, लेकिन निवेश टाल रही है
- यानी पैसा मैदान में नहीं उतर रहा= Capital on the bench
- वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई चेंज ना करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये बदलाव इस साल उनकी प्राथमिकता में नहीं थे।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड पर क्या बदला?

सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स छूट के नियम स्पष्ट और सीमित करने का फैसला किया है। यह छूट केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने SGB को मूल इश्यू के समय सब्सक्राइब किया और मैच्योरिटी तक होल्ड किया।

फॉर्म 15G और 15H पर नियम

फॉर्म 15G और 15H जमा करने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी। अलग-अलग कंपनियों में निवेश रखने वालों को बार-बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। NSDL और CDSL डिपॉजिटरी एक ही प्लैटफॉर्म पर ये फॉर्म स्वीकार करेंगी।

राहत आयकर कानून में बड़ा सुधार, टैक्सपेयर्स की आसानी मकसद

सज़ा की अवधि में कटौती, कई मामले अपराध की कैटिगरी से बाहर

एक्सपर्ट व्यू

सीए लक्ष्य शर्मा, इनकम टैक्स एक्सपर्ट

- सरकार ने आयकर कानून के तहत दंड प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां कुछ मामलों में सात साल तक की कैद का प्रावधान था, उसे अब घटाकर अधिकतम दो साल कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, अगर टैक्स की राशि 10 लाख रुपये तक है तो किसी प्रकार की कैद नहीं होगी। वहीं 10 लाख से 50 लाख रुपये तक के मामलों में अधिकतम छह महीने की सजा का प्रावधान रखा गया है और इससे अधिक राशि पर दो साल तक की कैद हो सकती है।

इसके अलावा टीडीएस का भुगतान न करने पर भी अब अधिकतम सजा दो साल तक सीमित कर दी गई है। सरकार ने कुछ अपराधों को पूरी तरह से डिक्रिमिनलाइज भी कर दिया है, जैसे ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स से होने वाली जीत पर टीडीएस काटना भूल जाने पर पहले सात साल तक की सजा थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। यह कदम कर व्यवस्था को सरल और व्यावसायिक अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

AI Image

ईपीएफ से जुड़े मामलों में मुकदमेबाज़ी पर क्या असर होगा?

कर्मचारियों से काटा गया ईपीएफ एम्प्लॉयर को ईपीएफ खाते में जमा करना होता है। अगर वह समय पर जमा नहीं करता तो वह इनकम में जोड़ना पड़ता है। जमा करने की ड्यू डेट ईपीएफ के प्रावधानों से ली जाती थी। अगर जमा करने में एक दिन की भी देरी होती थी तो टैक्स देना पड़ता था। इनकम टैक्स के दूसरे प्रावधानों में किसी भी सरकारी ड्यू को रिटर्न भरने की डेट से पहले जमा कर देने पर उसे इनकम में नहीं जोड़ा जाता था। इस विषय को लेकर काफी मुकदमेबाजी होती थी। अब यह फैसला लिया गया है कि ड्यू डेट रिटर्न भरने की डेट मानी जाएगी। इससे मुकदमेबाजी खत्म होगी।

एक्सिडेंट क्लेम मुआवज़े पर ब्याज भी टैक्स फ्री

बजट में मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) से जुड़े पीड़ितों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड से मिलने वाली मूल मुआवजा राशि पहले से ही टैक्स फ्री थी, लेकिन जब राशि देर से मिलती थी और उस पर कुछ ब्याज मिलता था तो उस ब्याज को अन्य स्रोतों से आय मानकर टैक्स लगाया जाता था। उस ब्याज पर टीडीएस भी काटा जाता था। नए प्रावधान के तहत सरकार ने इस ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त कर दिया है। इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। MACT द्वारा दिए गए मुआवजे के ब्याज पर टीडीएस लागू हो या नहीं? यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में 50,000 से अधिक मुआवजे के ब्याज पर टीडीएस लागू करने के मामले में केंद्र सरकार से विचार मांगे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राधा स्वामी सत्संग (ब्यास) के संरक्षक से की शिष्टाचार भेंट

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सांगानेर के बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग केन्द्र पहुंचकर हुजूर जसदीप सिंह गिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग (ब्यास) के संरक्षक गिल का शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर विधायक फूल सिंह मीना सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे।

राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच

ईवीएम उपलब्धता को लेकर एडिशनल एमओयू हस्ताक्षर

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारु, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य मंगलवार को सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त समझौता ज्ञापन (एडिशनल एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एम.ओ.यू. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित पूर्व में किए गए समझौते का विस्तार है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस एडिशनल एम.ओ.यू. के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ईवीएम का उपयोग प्रदेश में नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा एवं वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आपसी समन्वय एवं सहयोग संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करने के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की सुरक्षा, परिवहन, भंडारण एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित प्रोटोकॉल के तहत सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण (एफ.एल.सी.), मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। एडिशनल एम.ओ.यू. में यह भी प्रावधान किया गया है कि ईवीएम के परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा व्यवस्था तथा तकनीकी स्टाफ की यात्रा से संबंधित व्यय की वहन व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।

मुख्यमंत्री की पहल से ग्रामीण सशक्तिकरण की नई इबारत

प्रदेशभर में ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल के तहत कृषकों, पशुपालकों एवं ग्रामीण नागरिकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेशभर में गिरदावर सर्किल स्तर पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 1512 गिरदावर सर्किलों में इन शिविरों का सफल आयोजन कर राज्य सरकार के 13 प्रमुख विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं को एक ही मंच पर आमजन तक पहुँचाया गया है। इन शिविरों में ग्रामीणों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन-पत्र तैयार करवाने, पूर्व में दिये गए आवेदनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी, दस्तावेज़ सत्यापन एवं ऑन-द-स्पॉट मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि विकास की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँचे। इसी क्रम में द्वितीय चरण के शेष ग्राम उत्थान शिविर आयोजन 5 से 9 फरवरी तक किया जा रहा है।

पशुपालकों को बड़ा लाभ

शिविरों के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 92 हजार पशुओं का पंजीकरण कर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इसके साथ ही क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाव हेतु 77 हजार से अधिक टीके, 5,352 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 26,400 से अधिक फर्टिलिटी किट का वितरण तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा एवं कृमिनाशक औषधि पिलाई गई।

कृषकों के लिए सहयोग

कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि विपणन विभाग द्वारा 6 लाख 37 हजार से अधिक किसानों को एमएसपी जानकारी दी गई, वहीं 7 लाख 42 हजार कृषकों को विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त 98 हजार से अधिक सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, 2,800 से अधिक ग्राम पंचायतों में पॉलीहाउस हेतु आवेदन तैयार किए गए तथा 2,923 किसानों के मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायतार्थ योजनान्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

14,600 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव की तैयारी, एलान अगले माह

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। प्रदेश में पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच मार्च के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही आरक्षण लागू करने और लॉटरी प्रक्रिया भी इसी महीने पूरी कर ली जाएगी।पंचायत चुनाव में आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया वह मुख्य चरण हैं जो यह तय करते हैं कि कौन सी सीट (सरपंच, वार्ड पंच, या जिला प्रमुख) किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

वोटर लिस्ट का काम अंतिम चरण में

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, राज्य में पहले फेज में 14,600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव होंगे। कमीशन लेवल पर वोटर लिस्ट को फ़ाइनल किया जा रहा है। जिसके साथ ही यूनिट वाइज वोटर लिस्ट बनाने का काम फ़ाइनल स्टेज में है और सूचियों पर आपत्तियां भी मांगे गए हैं।

मार्च में पूरी होगी लॉटरी प्रक्रिया

इसके बाद सूत्रों के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सात दिन के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद सीटों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मार्च महीने में ही पूरी कर ली जाएगी।

कार्यकाल और चुनाव पर होगा फैसला

प्रदेश में 12 जिला परिषदों और उनसे जुड़ी पंचायत समितियों के भविष्य पर सरकार को बड़ा फैसला लेना है। इन परिषदों का कार्यकाल इसी वर्ष सितंबर से दिसंबर के मध्य समाप्त होने वाला है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पास कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पूर्व ही बोर्ड को भंग करने का कानूनी अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, नियत समय के बाद गठित की गई नई ग्राम पंचायतों में चुनाव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

नई पुलिस चौकियां खोलने के लिए सर्वेक्षण पूर्ण

आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सुभाष चौक थाना वर्तमान में बेहद सीमित जगह पर संचालित है। आस-पास उपयुक्त खाली भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे स्थानान्तरित करने के लिए भूमि चिह्नित नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि सघन इलाकों में पुलिस चौकियां खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नई पुलिस चौकियां खोलने पर विचार किया जाएगा।

गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुन्दाचार्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चार दरवाजा बारियों के बाग स्थित खाली जमीन निजी भूमि होने के कारण सुभाष चौक थाना को यहां पर स्थानान्तरित किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर पारिवारिक विवाद चल रहा है तथा उच्च न्यायालय का स्टे है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बेढ़म ने कहा कि वर्तमान में इस भूमि पर बाउन्ड्री वॉल नहीं है। कुछ पड़ोसियों द्वारा अपने दरवाजे इस भूमि पर खोले गए हैं, जिसके संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार आवासीय भवन सहित पुलिस थाने के लिए 5 हजार वर्ग मीटर तथा आवासीय भवन रहित पुलिस थाने के लिए 3 हजार वर्ग मीटर जमीन होनी आवश्यक है।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जयपुर शहर का पुलिस थाना सुभाष चौक अत्यन्त सीमित जगह पर संचालित है। वर्तमान में पुलिस थाना सुभाष चौक के मालखाना, बैरिक व मैस का संचालन थाने के सामने स्थित धर्मशाला में निःशुल्क किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चार दरवाजा बारियों का बाग स्थित भूमि वर्तमान में खाली है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय D.B. Civil Writ Petition No. 9466/2014एवं न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 07 जयपुर महानगर में दीवानी विविध अपील संख्या 12/2019 में वाद चल रहा है। जिसके कारण पुलिस थाना सुभाष चौक को वर्तमान में उक्त भूमि पर स्थानान्तरित किया जाना संभव नहीं है।

कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों को कक्षा ग्यारहवीं ने दी भावभीनी विदाई

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। एन. के. पब्लिक स्कूल, मुरलीपुरा कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन स्कूल ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कक्षा ग्यारहवीं के विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर अपने सीनियर्स का पारंपरिक स्वागत कर किया।

कार्यक्रम की शुरुआत उत्साहपूर्ण जैम सेशन एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। रोणक एवं समूह, खुशबू, रिधिमा एवं युविका समूह, हंशिका समूह, नंदिनी एवं संजना, ईशा एवं समूह , निखिल एवं समूह द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिसने पूरे सभागार को उत्साह और उल्लास से भर दिया। वहीँ माधव उपाध्याय द्वारा गाए गए 'अभी ना जाओ छोड़कर' गीत ने सभी की आँखों में आँसू ला दिए। कक्षा बारहवीं के विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा रैंप वॉक प्रस्तुत किया गया।

कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों ने विद्यालय एवं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माइक सेट एवं ट्राइपॉड भेंट किए। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर निदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि, "आप सभी हमारे विद्यालय की धरोहर हैं। यहाँ प्राप्त शिक्षा और संस्कार आपको जीवन में ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगे। सदैव अनुशासन, मेहनत और मूल्यों को अपना मार्गदर्शक बनाइए। हमें गर्व है कि आप एन. के. पब्लिक स्कूल के छात्र रहे हैं।"

प्रबंध निदेशक डॉ नेमीचंद लुनायच ने अपने आशीर्वचन में कहा कि, "जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आज आप विद्यालय से विदा ले रहे हैं, परन्तु सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अंत में

डीएनटी पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर अब 15 तक

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश भर में घुमन्तु समुदाय (विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु) के लिए चलाए जा रहे पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर आगामी 15 फरवरी संचालित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में घुमंतु समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी करने के लिए 12 से 31 जनवरी तक पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर संचालित किए गए थे। समुदाय के प्रतिनिधियों की मांग और ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किए जाने के लिए इन शिविरों की तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। गहलोत ने कहा कि शिविरों के आरंभ होने से अबतक ई मित्र पोर्टल पर डीएनटी पहचान पत्र के लिए कुल 10 हजार 764 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5 हजार 378 लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष में से 1 हजार 301 आवेदन, आवेदकों को विभिन्न आक्षेपों या कमी पूर्ति दूर करने के लिए लौटाए जा चुके हैं।

मुख्य सचिव ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र IPS अधिकारियों से किया संवाद

केंद्रीय स्तर पर प्राप्त अनुभव राज्य प्रशासन को भी सशक्त बनाता है- मुख्य सचिव

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति न केवल कैडर की जिम्मेदारी है, बल्कि यह अधिकारियों के करियर विकास का भी महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्राप्त अनुभव राज्य प्रशासन को भी सशक्त बनाता है। मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के साथ आयोजित संवादात्मक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने पात्र अधिकारियों को अपने करियर की योजना बनाते हुए समयबद्ध एवं सोच-समझकर निर्णय लेने तथा केंद्रीय सेवाओं में योगदान देने के लिए कहा।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 बैच से आगे के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे एसपी अथवा डीआईजी स्तर पर न्यूनतम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूर्ण कर चुके हों, जिससे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें केंद्र सरकार में कार्य का अनुभव प्राप्त हो सके। बैठक के दौरान कार्मिक विभाग द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न स्तरों- एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी एवं डीजी पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता की जानकारी के साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि, पदोन्नति के दौरान संयुक्त कार्यकाल, कठिन क्षेत्रों में सेवा देने पर अवधि विस्तार, प्रशिक्षण अवधि की गणना, कूलिंग-ऑफ अवधि, प्रत्यावर्तन एवं डिबारमेंट से जुड़े प्रावधानों को भी बताया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं केंद्रीय संगठनों में आईपीएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत पदों एवं वर्तमान रिक्तियों की स्थिति की भी जानकारी साझा की गई, जिससे अधिकारियों को उपलब्ध अवसरों का स्पष्ट ब्यौरा मिल सके। बैठक में शासन सचिव, कार्मिक विभाग अर्चना सिंह सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों एवं इकाइयों से आईपीएस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सहभागिता की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण का नया अध्याय

राज्य सरकार की ठोस नीतियों से सामाजिक न्याय के नए आयाम स्थापित

छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, गुरुकुल योजना से एमबीसी विद्यार्थियों के लिए खुले शिक्षा के नए द्वार

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर कौशल विकास तक समाज के युवाओं को मिला सशक्त मंच

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मजबूत राह पर अग्रसर है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और ठोस नीतियों के परिणामस्वरूप अति पिछड़ा वर्ग के हजारों परिवार न केवल विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, संबल और सम्मान के जरिए सामाजिक न्याय के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं।

छात्रवृत्ति योजनाओं से हजारों विद्यार्थियों को मिला संबल

मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों पर वर्ष 2025 में 248 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 102.42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय कर 37 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6 से 10) में 7.10 करोड़ रुपए व्यय कर 69 हजार से अधिक विद्यार्थियों को सहायता दी गई है।

बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष पहल

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एमबीसी छात्राओं के लिए करौली के नादौती एवं भरतपुर के बयाना में छात्रा महाविद्यालय मय हॉस्टल की स्थापना की गई है। नादौती कॉलेज में 74.80 लाख रुपए व्यय कर 177 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह बयाना कॉलेज में 155.29 लाख रुपए व्यय कर 543 छात्राओं को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हुआ है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग हुआ प्रशस्त

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को आईएएस, आरएएस, क्लैट, नीट, रीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित संस्थाओं में कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में 4 करोड़ रुपए व्यय कर विद्यार्थियों को भविष्य की तैयारी का सशक्त मंच दिया गया है।

देवनारायण छात्रावास योजना से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव मजबूत

देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों के प्रवेश के प्रावधान वाली इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जा चुका है। इसी तरह देवनारायण छात्रावास योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों में 3750 विद्यार्थी तथा देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना के तहत स्वीकृत विद्यालयों में 5 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

कौशल विकास से रोजगार की ओर कदम

इसी तरह देवनारायण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 6 आईटीआई संस्थानों में 365 लाख रुपए व्यय कर 500 से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग का सशक्तीकरण केवल योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की जीवंत मिसाल बन चुका है।

सम्पादकीय

यूजीसी के नये नियमों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशंस क्या भारतीय संविधान के विपरीत है? इस बात की जांच अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कुछ अपीलकर्ताओं ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि यूजीसी के नये नियम जेनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं, उन अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलवक्त नये नियमों पर रोक लगा दी है और 2012 के नियमों को ही जारी रखा है। यूजीसी के नये नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि फिलहाल 2012 के नियम ही प्रभावी होंगे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा है कि नियमों में कुछ अस्पष्टता है, जिसकी वजह से इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करने के लिए कहा है। यूजीसी के नये नियमों पर जेनरल कैटेगरी के लोगों ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह भेदभाव पूर्ण है और इसका गलत इस्तेमाल सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ किया जा सकता है। दरअसल यूजीसी ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्या के बाद संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए नये नियम 13 जनवरी को जारी किये थे, जिसमें एससीङ्कएसटी के साथ ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल किया था। इस नियम का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले लोगों को जाति आधारित भेदभाव से बचाना था। लेकिन जेनरल कैटगरी के लोगों ने इसे भेदभाव पूर्ण बताया, क्योंकि इस नियम में गलत शिकायत दर्ज करने वालों के लिए किसी भी तरह की सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जेनरल कैटेगरी के लोगों ने यूजीसी के नये नियमों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया और इन नियमों को जेनरल कैटेगरी की प्रताड़ना का जरिया तक बताया। यूजीसी ने 2012 में संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए एक नया कानून बनाया था, जिसके तहत एससीङ्कएसटी वर्ग से आने वाले लोगों को जाति आधारित भेदभाव से बचाने के लिए नियम बनाए गए थे। इस नियम का उद्देश्य अनुशासन कायम करना है, ताकि जातिगत भेदभाव ना हो। यह नियम बहुत सख्त नहीं थे और इसमें गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई और दंड का प्रावधान था। यूजीसी के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। यूजीसी के नये नियमों के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान कोर्ट गए हैं और इन नियमों को जेनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण बताया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि नये नियमों पर रोक इसलिए लगाई जा रही है ताकि इसकी संवैधानिकता की जांच हो। कोर्ट इस बात को देखेगा कि क्या नये नियमों में संविधान के खिलाफ कुछ भी है या नहीं, उसके बाद ही यह नियम लागू हो पायेंगे या यह भी संभव है कि इसमें कुछ संशोधन हो। सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी के नये नियमों की जांच करेगा और यह देखेगा कि क्या नियम जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा है। इसकी वजह यह है कि संविधान में इस तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है।

वित्त मंत्री यह वादा कर सकती हैं कि ऋण-जीडीपी अनुपात को मौजूदा वर्ष के 56.1 फीसदी से कम करके 2026-27 में 55.6 फीसदी किया जाएगा। यह अपेक्षा से धीमा है। राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के 4.4 से घटकर 4.3 फीसदी हो जाएगा। राजकोषीय एकीकरण के प्रति गत दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं।

बजट-संतुलित घाटा और सर्विस सेक्टर से विकास की उम्मीद

तुषार पुरोहित
पत्रकार
@jagrukjanta.net

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

इस वर्ष एक ओर, वैश्विक दबाव काफी अधिक हैं और वित्त मंत्री शायद प्रणाली को झटका देना पसंद न करें, खासकर तब जबकि कुछ प्रणालियां, जैसे जीएसटी प्राप्तियां, संकट का संकेत दे रही हों।

वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट असाधारण भूराजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रस्तुत किया गया। भारत की वृद्धि दर 7.4 फीसदी के साथ मजबूत बनी रही लेकिन आगे इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। बीते कई सालों से सरकार का रुख सार्वजनिक निवेश को वृद्धि को बढ़ावा देने में प्रयोग करने का रहा है। इस वर्ष बुनियादी ढांचे पर होने वाला व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये होने जा रहा है जो काफी अधिक है। इसके साथ ही नई और बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए दृष्टिकोण में भी विस्तार किया गया है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से विभिन्न विकास केंद्रों को जोड़ने वाली नई उच्च गति की रेल लिंक श्रृंखला, पूर्व-पश्चिम धुरी पर नए समर्पित मालवाहक गलियारे, तटीय माल परिवहन, जिससे रेल और राजमार्गों पर दबाव कम हो सके और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, जिनका उद्देश्य आंतरिक क्षेत्रों से खनिज संपदा को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाना है। यह बात ध्यान देने लायक है कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा ब्याज रहित ऋण में इजाफे के रूप में है जो राज्यों को उनके ही निवेश के लिए दिया जाता है।बहरहाल, फैक्टरियों और परियोजनाओं में निजी निवेश ने सरकारी निवेश को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी और रोजगार वृद्धि सीमित बनी रही। सरकार ने विनिर्माण पर जो जोर दिया उसे निस्संदेह कुछ कामयाबी मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा दौर शुरू किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के आवंटन को 23,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। मेक इन इंडिया को प्रतिकूल हालात का सामना करते रहना होगा। इसमें मौजूदा कारोबारी तनाव भी शामिल हैं। बजट 2026 में सेवा क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है।

एक उच्चस्तरीय समिति का प्रस्ताव रखा गया है जो सेवा क्षेत्र में 'शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता' तक रोजगार और उत्पादन पर ध्यान देगी। आईटी सक्षम सेवाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा, सामाजिक देखभाल और रचनात्मक क्षेत्रों तक कई सेवा क्षेत्रों की सहायता के लिए बजट समर्थन की घोषणा की गई। इसमें नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से लेकर नए संस्थानों के लिए सब्सिडी सहायता तक शामिल हैं। यह परिवर्तन सरकार की व्यापक चिंता को दर्शा सकता है। यह चिंता नई विनिर्माण इकाइयों में निजी निवेश की कमी, नए कारखानों की बढ़ती पूंजीगत लागत और भारतीय वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं से संबंधित है। सेवा क्षेत्र को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।

हालांकि, इसमें कार्यबल में उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करना ही इन नई पहलों का मूलभूत विषय प्रतीत होता है। फिर भी यह उचित प्रश्न है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की क्रांति इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर कितना प्रभाव डालेगी क्योंकि अब सरकार अपना ध्यान इन पर केंद्रित कर रही है। मौजूदा सरकार की आर्थिक नीति का दूसरा प्रमुख स्तंभ, पूंजीगत व्यय के अलावा राजकोषीय संयम भी रहा है। बजट 2026 पर्यवेक्षकों को अपेक्षाकृत विरोधाभासी संकेत देता है। यह पहला साल है जब औपचारिक लक्ष्य अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे से हटकर ऋण-जीडीपी अनुपात पर केंद्रित किया गया है, जिसे अब 'ऋण लक्ष्य निर्धारण के लिए परिचालन साधन' के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है। इससे विश्लेषण कुछ जटिल हो जाता है, क्योंकि अब भविष्य में जीडीपी की दिशा और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है। बजट अगले वर्ष के लिए 10 प्रतिशत नॉमिनल वृद्धि मानकर चलता है, जो इस वर्ष से थोड़ी अधिक है । इसमें यह भाव निहित है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति इस वर्ष कुछ अधिक होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि वित्त मंत्री यह वादा कर सकती हैं कि ऋण-जीडीपी अनुपात को मौजूदा वर्ष के 56.1 फीसदी से कम करके 2026-27 में 55.6 फीसदी किया जाएगा। यह अपेक्षा से धीमा है। राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के 4.4 फीसदी से घटकर 4.3 फीसदी हो जाएगा। ये बहुत छोटे बदलाव हैं और राजकोषीय एकीकरण के प्रति गत दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं। इस वर्ष एक ओर, वैश्विक दबाव काफी अधिक हैं और वित्त मंत्री शायद प्रणाली को झटका देना पसंद न करें, खासकर तब जबकि कुछ प्रणालियां, जैसे जीएसटी प्राप्तियां, संकट का संकेत दे रही हों। दूसरी ओर, ऋण का गणित प्रतिकूल है क्योंकि पिछले उधार की कई किश्तें इस वर्ष परिपक्व होंगी। शुद्ध उधारी केवल मामूली रूप से बढ़ेगी, सकल बाजार उधारी तेजी से बढ़कर 17.2 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, जो 14.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इससे स्वाभाविक रूप से बॉन्ड बाजार पर काफी दबाव पड़ेगा और यील्ड तथा दरों पर बोझ बनेगा। जहां तक सामान्य निवेशक, छोटे व्यवसायी और उपभोक्ताओं का सवाल है, सरकार की कार्रवाई का ध्यान तंत्र और शासन को आसान बनाने पर केंद्रित है। यह स्वागत योग्य है। बजट में जो वादे किए गए हैं उनमें छोटे उद्यमों के लिए ट्रेड्स प्रणाली के उपयोग का विस्तार, कई कर अपराधों को अपराध मुक्त बनाना और कुछ चूकों (जैसे विदेशी संपत्तियों के लिए) पर प्रतिरक्षा प्रदान करना, भरोसे पर आधारित कस्टम्स के लिए नए दृष्टिकोण का वादा और व्यक्तिगत यात्रा के लिए शुल्क मुक्त भत्तों का संशोधन शामिल हैं। एक चीज जिसे सख्त किया गया है, वह है वायदा एवं विकल्प कारोबार पर प्रतिभूति लेनदेन कर। कुछ बड़े बाजार प्रतिभागी चिंतित हैं कि इससे नकदी कम होगी लेकिन तथ्य यह है कि खुदरा व्यापारी इन जटिल लेन-देन में अत्यधिक शामिल हो रहे थे, और वायदा एवं विकल्प में लग रही तिकड़मों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक था। कुल मिलाकर, बजट 2026 इस दांव पर आधारित है कि धीमा राजकोषीय एकीकरण, राज्य का पूंजीगत व्यय और सेवाओं को बढ़ावा देना विकास को जारी रखेगा।

वैक्सीन खोलेगी कैंसर के निदान की राह

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

वैक्सीन खोलेगी कैंसर के निदान की राह - कैंसर से बचने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। इसमें तंबाकू, धूम्रपान से दूरी, संतुलित और पौष्टिक आहार, रोजाना व्यायाम, संतुलित वजन और नियमित हेल्थ चेकअप शामिल हैं। वहीं सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से त्वचा की रक्षा करना भी आवश्यक है।

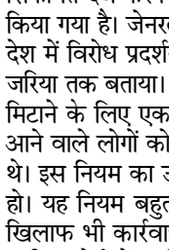

डॉ. मोनिका शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

हाल ही में रूस ने एक कैंसर की वैक्सीन का अविष्कार करने का दावा किया है। उसका कहना है कि यह परीक्षणों में सफल रही है और अगर इसे प्रशासनिक मंजूरी मिलती है, तो वैश्विक स्तर पर मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन रही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का जड़ से खात्मा किया जा सकेगा। अगर ये संभव हुआ तो देश-दुनिया में कैंसर पीड़ितों के लिए बड़ी राहत होगी। यह वैक्सीन एमआरएनए तकनीक पर आधारित है, जो कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल हुई थी। खास बात ये है कि यह पर्सनलाइज्ड यानी मरीज (केस स्टडी) के लिए व्यतिगत तौर पर तैयार की सकेगी। असल में रूस ने एंट्रोमिक्स नामक एक एमआरएनए आधारित, पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हर मरीज के ट्यूमर के हिसाब से बनती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसने प्री-क्लिनिकल परीक्षणों में सौ फीसदी प्रभावशीलता दिखाई है और शुरुआती मानव परीक्षणों में भी सफल रही है। खासकर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। इससे पहले एमआरएनए तकनीक का उपयोग कोविड वैक्सीन में भी किया गया था।

बात करें कैंसर कि तो ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप लेकर आस-पास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं। देश-दुनिया मे अब तक 200 से अधिक कैंसर के प्रकार की पहचान की जा चुकी है। ये विभिन्न अंगों जैसे स्तन, फेफड़े, मुंह में उत्पन्न होते हैं। हर

प्रकार का कैंसर एक-दूसरे से भिन्न हो सकता है। कैंसर के प्रमुख प्रकारों में कार्सिनोमा सबसे आम प्रकार है, जो त्वचा या अंगों की परत में शुरू होता है जैसे स्तन, फेफड़े। दूसरा सारकोमा यह हड्डी, उपास्थि, वसा या मांसपेशियों में शुरू होता है। तीसरा प्रकार ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसर है, जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। चौथा प्रकार लिम्फोमा जो लिम्फ प्रणाली में शुरू होता है। पांचवा मेलानोम है, जो त्वचा की कोशिकाओं में शुरू होता है। भारत में प्रमुख रूप से मुंह, गला, स्तन, फेफड़े, पेट और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर अधिक देखने को मिलते हैं। कैंसर पर दुनियाभर के हालिया सर्वे और रिपोर्ट्स बताते हैं कि कैंसर का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के आंकड़ों के अनुसार, कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। वैश्विक कैंसर परिदृश्य में 2022 में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए और 9.7 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई। 2050 तक नए मामलों की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2022 की तुलना में बहुत अधिक है। 2022 में फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा पाया गया। इसके बाद स्तन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर का स्थान है। कैंसर से होने वाली मौतों में फेफड़ों का कैंसर सबसे आगे है। इसके बाद कोलोरेक्टल आंत और लिवर कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें हुईं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले चीन में दर्ज किए गए हैं। वहां लगभग 48 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अमेरिका इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां 2025 में 20 लाख से अधिक नए मामले सामने आने का अनुमान लगाया गया। भारत में भी कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह विश्व में तीसरे प्रमुख देशों में से एक है। 2025 के सर्वेक्षणों के अनुसार, उच्च आय वाले देशों में कैंसर की दर सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कैंसर की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्किन कैंसर है। यूरोप, डेनमार्क, आयरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस में भी कैंसर की उच्च दर है। कैंसर पर हुए सर्वेक्षण में जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों को इस बीमारी के बढ़ने का प्रमुख कारण बताया गया है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जिनमें धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और खराब आहार (ज्यादा फैट, चीनी) कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण (प्लास्टिक में मौजूद टॉक्सिंस) भी कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। विकासशील देशों में ह्यूमन पैपिलोमावायरस और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमण भी कैंसर विशेषकर गर्भाशय ग्रीवा और लिवर कैंसर के बड़े कारण हैं।

आखर-आखर झरे उजियार

सकारात्मक भावों का संचारः बनाये सुखमय यह संसार

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

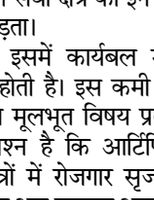

गोपाल प्रभाकर
पत्रकार
@jagrukjanta.net

अत्र कुशलम, तत्रास्तु। यहां हम सब राजी खुशी हैं। आशा है, आप भी वहां भगवतकृपा से राजी खुशी होंगे... यहां हम सकुशल हैं, आपकी कुशलता ईश्वर से नेक चाहते हैं। इस तरह की इबारत से पुरानी चिट्ठी पत्री का शुभारंभ हुआ करता था। आज तो मोबाइल पर संदेश (sms) तुरन्त प्रेषित हो जाते हैं। तत्काल संदेशों का आदान-प्रदान हो जाता है, लेकिन अब चिट्ठी पत्री की खुशबू कहीं खो गई है। वो खतो किताबत और पत्र का बेसब्री से इंतजार कि डाकिया आएगा। कुछ नया सन्देशा लाएगा, जैसे बीत गए सपने सा लगता है।

ये परिवार के ताज़ा समाचारों की ही नहीं, मन के विचारों की भी सुखद यात्रा हुआ करती थी। पत्र लिखने वाला भी जमा जमा कर सुन्दर सुलेख से अपना प्रभाव प्रसारित करता था। सकारात्मक विचारों से हम एक दूसरे को आश्वस्त करते थे,परस्पर स्पंदित हुआ करते थे। वो ज़माने गए, यह कह कर हम मनोभावों की अमूल्य सम्पदा को खारिज नहीं कर सकते। अभी भी हमारे घरों में कहीं बुजुर्गों की चिट्ठी मिल जाएगी, जिसे पढ़ कर आंखे नम हो जाएंगी। कितना प्यार दुलार, नसीहत और दुआओं का खज़ाना उसमें मेहसूस होता है।

दरअसल सकारात्मक भावों का संचार हमारे लिए सुखमय संसार की सृष्टि करता है।ये सकारात्मक भाव मन से होने चाहिए, नहीं तो असरदार नहीं होते। आप ऊपर से तो शालीन भाषा में कुछ भी बोलें या लिखें लेकिन मन में वो बात नहीं हो तो असर कैसे होगा? मन की तरंगें भी तो उस व्यक्ति या गन्तव्य तक पहुंचेगी। बात प्रभावी तब ही होगी, जब मनसा वाचा कर्म के स्तर से एक लय होकर बात निकलेगी। फिर यह स्वभाव की विभिन्नता पर निर्भर करता है कि कौन किस मंशा से कार्य करे।भर्तहरि के नीति शतक में लिखा है कि इस संसार में कई प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। प्रथम तो देव मानव जो अपने जीवन की बाजी लगा कर दूसरे का भला करते हैं। दूसरे वो साधु प्रकृति मनुष्य जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनकी स्वयं की हानि न हो। तीसरे वे आसुरी प्रकृति के लोग जो अपनी भलाई के लिए दूसरों की हानि करने से नहीं चूकते। चौथे वो जो बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसा करने में उनका कोई लाभ नहीं होता, यह तो उनका स्वभाव ही होता है। योगक्षेम का सर्वोत्तम सन्देश भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में दिया है।वो कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर का निरन्तर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं,उन नित्य निरन्तर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं।

ओपिनियन

वसीयत में ज़हर : विकास की चिता पर जलती हमारी अगली पीढ़ी की सांसें

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

मणिमाला शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

भारत आज जिस 'विश्वगुरु' और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न देख रहा है, उसकी नींव में एक ऐसी खामोश विभीषिका पल रही है, जिसका जिक्र सत्ता के गलियारों में कम ही होता है। देश के महानगरों से लेकर औद्योगिक कस्बों तक, हवा अब जीवन का आधार नहीं बल्कि 'कार्सिनोजेनिक' तत्वों का वाहक बन चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण अब केवल सर्दियों की 'हेडलाइन' नहीं रह गई बल्कि एक स्थायी 'मेडिकल इमरजेंसी' हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (NCR) का इलाका वर्षों से इस धुंध की चपेट में है। जहाँ 'स्मॉग' अब एक प्रकार का वार्षिक उत्सव बन चुका है। लेकिन इस राष्ट्रीय त्रासदी का सबसे वीभत्स और डरावना चेहरा आज राजस्थान में उभरकर सामने आ रहा है। मरुधरा की वह हवा, जो कभी अपनी शुष्कता और शुद्धता के लिए जानी जाती थी, आज विकास की अंधी दौड़ और प्रशासनिक पंगुता के कारण एक ऐसे 'गैस चैंबर' में तब्दील हो चुकी है जिसकी मार दिल्ली से भी अधिक घातक है।

देश का संकटः आंकड़ों की ज़ुबानी

यदि हम पूरे भारत के परिदृश्य पर नज़र डालें, तो स्थिति सिहरन पैदा करने वाली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (NCRP) के 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कैंसर के कुल मामलों में फेफड़ों का कैंसर अब सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर बन गया है। देश में हर साल फेफड़ों के कैंसर के लगभग 1.2 से 1.5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। सबसे भयावह तथ्य यह है कि भारत में इस बीमारी से होने वाली मृत्यु दर (Mortality Rate) दुनिया में सबसे अधिक है, क्योंकि लगभग 75 प्रतिशत मामलों का पता तीसरी या चौथी स्टेज पर चलता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक और चौंकाने वाला ट्रेंड यह भी है कि भारत में फेफड़ों के कैंसर के कुल मरीजों में 50 प्रतिशत से अधिक वे लोग हैं जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। वैश्विक स्तर पर यह औसत केवल 10-15 प्रतिशत है, जो स्पष्ट करता है कि भारतीयों के फेफड़े बाहरी प्रदूषण से अधिक छलनी हो रहे हैं। 'द लैंसेट' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक मौतें प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं, जो देश की कुल मौतों का लगभग 18 प्रतिशत है। यह किसी भी सीमावर्ती युद्ध या महामारी से कहीं अधिक बड़ा मानवीय नुकसान है।

राजस्थान आज देश के इसी श्वसन संकट का 'महाकेंद्र' (Epicenter) बन गया है। यदि हम राज्य के कैंसर संस्थानों और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) के श्वसन विभागों के गलियारों में टहलें, तो एक ऐसी सच्चाई उभरकर आती है जो पूरे देश के लिए चेतावनी है। राजस्थान में पिछले पाँच सालों (2021-2026) के भीतर फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की संख्या में जो उछाल आया है, वह किसी भी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से अधिक भयावह है। चिकित्सा सांख्यिकी के अनुसार, राज्य में फेफड़ों के कैंसर के मरीजों में वार्षिक 35 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ 'नॉन-स्मोकर्स' में बढ़ता कैंसर ही वह बिंदु है, जहाँ से इस संकट की परतें खुलना शुरू होती हैं। राजस्थान में फेफड़ों के कैंसर के नए मामलों में लगभग 42 प्रतिशत की हिस्सेदारी अब उन लोगों की है जिनका धूम्रपान का कोई इतिहास नहीं है। इस त्रासदी का सबसे भयावह चेहरा राजस्थान के उस औद्योगिक गलियारे में दिखाई देता है जो दिल्ली-एनसीआर की सीमा से सटा हुआ है। भिवाड़ी, जो अक्सर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली को भी पीछे छोड़ देता है, आज केवल एक औद्योगिक केंद्र नहीं बल्कि 'फेफड़ों की प्रयोगशाला' बन गया है। यहाँ 'पार्टिकुलेट मैटर' (PM 2.5) का स्तर अक्सर 450 से 500 के बीच रहता है। दिल्ली में जहाँ प्रदूषण का मुख्य कारण पराली और गाड़ियां बताई जाती हैं, वहीं भिवाड़ी और एनसीआर के राजस्थान वाले हिस्से में समस्या उद्योगों से निकलने वाला 'अघोषित धुआं' है। यहाँ 'व्हाइट लंग सिंड्रोम' की आवृत्ति में पिछले दो वर्षों में हुई 40 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि हमारा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र अब हार मान चुका है।थोड़ा आगे बढ़ें तो अजमेर जिले का किशनगढ़ अपनी 'सफेद चमक' के साथ स्वागत करता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी की यह चमक वास्तव में एक बड़े कब्रिस्तान की चादर है। यहाँ की हवा में मौजूद सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के सूक्ष्म कणों के कारण सिलिकोसिस के मामलों में पिछले पांच वर्षों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल के अनुसार, किशनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अब तक 25,000 से अधिक सिलिकोसिस पीड़ित पंजीकृत हैं। इनमें सबसे डरावना तथ्य यह है कि सिलिकोसिस से प्रभावित फेफड़ों में कैंसर होने की संभावना एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में 7 गुना अधिक होती है। राजधानी जयपुर की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। 'पिंक सिटी' अब धीरे-धीरे 'ग्रे सिटी' में तब्दील हो रही है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) के 'रियल-टाइम मॉनिटरिंग' डेटा के अनुसार, जयपुर के परकोटे और मानसरोवर जैसे इलाकों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) का स्तर पिछले पांच वर्षों में 22 प्रतिशत बढ़ा है। जयपुर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 'लंग कैपेसिटी' ग्रामीण बच्चों की तुलना में 22 प्रतिशत तक कम पाई गई है।इससे यह साबित होता है कि हम विकास के नाम पर एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो जवानी की दहलीज पर पहुँचने से पहले ही शायद इन्हेलर्स की मोहताज हो जाएगी। इस पर विडंबना यह है कि प्रशासन की प्रतिक्रिया हमेशा 'बैंड-एड' समाधान जैसी रही है। प्रदूषण बढ़ने पर निर्माण कार्य रोकना या स्कूल बंद करवा देना घाव पर केवल पट्टी बांधने जैसा है। विश्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण को ध्यान से देखें तो उसके अनुसार, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और कार्यक्षमता के नुकसान के कारण राजस्थान को अपनी कुल जीडीपी का लगभग 4.2 प्रतिशत हर साल गंवाना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्य है कि यह कैसा गणित है जहाँ लाभ के आंकड़ों के पीछे करोड़ों लोगों की साँसों का घाटा छिपा है?

हम सब जानते हैं कि सांस लेना कोई विकल्प नहीं है। इस संकट का समाधान केवल उपदेशों में नहीं, बल्कि कड़े प्रशासनिक हस्तक्षेप में है। एक्सपर्ट्स की मानें तो इसके समाधान के लिए भिवाड़ी और एनसीआर जैसे शहरों में स्तिथ उद्योगों के लिए 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' अपनानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर उनके वार्षिक टर्नओवर का 2-5% जुर्माना लगाया जाना होगा। इसके अलावा स्लरी निस्तारण का कानून बनाया जाए। किशनगढ़ में मार्बल स्लरी का वैज्ञानिक उपयोग अनिवार्य हो। स्लरी को खुले में डंप करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अर्बन फॉरेस्ट और EV ट्राज़िशन की जांच होनी चाहिए । जयपुर में 'मियावाकी तकनीक' से हर 2 किलोमीटर पर शहरी वन विकसित किए जाएं। परकोटे जैसे इलाकों को 'जीरो एमिशन ज़ोन' घोषित किया जाए। ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।

पंचांग

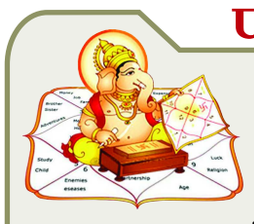

ज्योतिर्विद् अक्षय शास्त्री
साकेत पंचांग, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

जागरूक जनता पंचांग, नक्षत्र, तिथि, चौघड़िया

सूर्योदय-सूर्यास्त, तिथि

बुधवार, 04/02/2026

सूर्योदय : 07:14 **सूर्यास्त** : 18:06 **चन्द्रोदय** : 20:44 **चन्द्रास्त** : 08:39 **शक सम्वत** : 1947 विश्वावसु **अमान्ता महीना** : माघ **पूर्णिमांत** : फाल्गुन **सूर्य राशि** : मकर **चन्द्र राशि** : सिंह **पक्ष** : कृष्ण **तिथि** : तृतीया, 24:14 तक **वार** : बुधवार **द्रिक-वैदिक** : शिशिर **द्रिक-वैदिक अयन** : उत्तरायण **कलियुग** : 5126 वर्ष

नक्षत्र, योग, करण

नक्षत्र : पूर्व फाल्गुनी, 22:13 तक
योग : अतिगंदा, 25:06 तक
प्रथम करण : वणिजा, 12:23 तक
द्वितिय करण : विष्टि, 24:14 तक

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त	05:23 ए एम से
प्रातः सन्ध्या	05:49 ए एम से
अभिजित मुहूर्त	कोई नहीं
विजय मुहूर्त	02:24 पी एम से
गोधूलि मुहूर्त	06:00 पी एम से
सायाह्न सन्ध्या	06:03 पी एम से
अमृत काल	03:48 पी एम से
निशिता मुहूर्त	12:09 ए एम, फरवरी 05 से

निवास और शूल

दिशा शूल : उत्तर में
राहु काल वास दक्षिण-पश्चिम में
होमाहुति : मंगल
अग्निवास : पृथ्वी

चौघड़िया

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया
लाभ	: 07:13 - 08:35	उद्वेग : 18:06 - 19:44
अमृत	: 08:35 - 09:56	शुभ : 19:44 - 21:22
काल काल वेला	: 09:56 - 11:18	अमृत : 21:22 - 23:01
शुभ	: 11:18 - 12:39	चर : 23:01 - 00:39
रोग वार वेला	: 12:39 - 14:01	रोग : 00:39 - 02:18
उद्वेग	: 14:01 - 15:23	काल : 02:18 - 03:56
चर	: 15:23 - 16:44	लाभ : 03:56 - 05:34
लाभ	: 16:44 - 18:06	उद्वेग : 05:34 - 07:13

अमृत, शुभ, लाभ और चर को शुभ चौघडिया माना जाता है एवं उदवेग, काल एवं रोग को अशुभ चौघडिया माना जाता है।

आज तृतीया

आज कौन सा कार्य करें

तृतीया को यात्रा, शिल्प, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन व गृह प्रवेश शुभ है।

बुधवार को क्या करें

बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। यह भगवान गणेश और दुर्गा का दिन है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए।

ये कार्य करें :- सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। बुधवार को दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन जमा किए गए धन में बरकत रहती है। मंत्रणा, मंथन और लेखन कार्य के लिए भी यह दिन उचित है। ज्योतिष, शेयर, दलाली जैसे कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है।

यह कार्य न करें:- उत्तर, पश्चिम और ईशान में यात्रा न करें। बुधवार को धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है।

नोट : शुक्ल पक्ष में एक से पंचमी तक तिथियां अशुभ कही गई हैं, क्योंकि इन तिथियों में चंद्रमा क्षीण बल होता है और चंद्र बल उन दिनों नहीं रहने से कार्य सफल नहीं होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक तिथियों में चंद्र बल क्षीण होने से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।

राशिफल

माघ, कृष्ण, तृतीया, 2082 बुधवार, 4 फरवरी - 10 फरवरी, 2026

मेष [चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ]
अपनी जीवनशैली को सुधारने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक साहित्यों की ओर रुचि बढ़ सकती है। आयात-निर्यात के कारोबार में तेजी आयेगी। अधिकारी वर्ग आपकी अनदेखी कर सकते हैं।

तुला [रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते]
रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा। इवेन्ट मैनेजमेन्ट से जुड़े लोगों का काम आज बढ़ने वाला है।

वृषभ [ई,उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो]
कार्यक्षेत्र में नये दोस्त बन सकते हैं। परिवार में सुख-शान्ति का वातावरण रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति विश्वास बनाये रखें। तीर्थ यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपनी

वृश्चिक [तो,ना,नी, नू,या,यी,यू]
आय के नये स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। प्रेम सम्बन्धों का भरपूर आनन्द लेंगे।

मिथुन [क, की,कु,घ, ड,छ,के,को,ह]
परिजनों के साथ घूमने के लिये जा सकते हैं। आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्रोफेशनल जीवन से अधिक महत्व देंगे। जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करने के लिये दिन उत्तम है।

धनु [ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढ, भे]
कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जॉब में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी।

कर्क [हि, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो]
आप पर जिम्मेदारियाँ रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है। अपने खर्चों पर नियन्त्रण करने का दबाव रहेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाये रखें।

मकर [भो, जा,जी, जू, खा, खू, गा, गी,]
नयी जॉब ढूँढ रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी व्यक्तियों के साथ किसी गम्भीर विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दें।

सिंह [मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टु, टे]
दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। विदेश से जॉब के अवसर मिलने की सम्भावना है। वैवाहिक जीवन काफी रोमान्टिक रहेगा। बुद्धिमान लोगों के बीच आपका दायरा मजबूत होगा।

कुंभ [गू, गे, गो,सा, सी, सू, से, सो, दा]
नये कारोबार की शुरुआत करने के लिये दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिये विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी। रोगग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कन्या [टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो]
दिन का शुरुआती भाग आपके लिये काफी अच्छा रहेगा। सम्पत्ति के क्रय-विक्रय से बेहतरीन लाभ मिलेगा।

मीन [दी, दू, थे, झ, ञ, दे, दो, चा, चि]
अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरीपेशा को जॉब की चिन्ता हो सकती है। सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें।

आचार्य राजेश शास्त्री, जयपुर

विराट हिंदू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। बीते दिनों जेपी कॉलोनी लीलाधारी हनुमान मंदिर के सामने विराट हिंदू सम्मेलन समिति के तत्वाधान में अर्जुन बस्ती जिसमें जेपी कॉलोनी सेक्टर 4 जेडीए बापू बस्ती का क्षेत्र शामिल है के लोग भारी मात्रा में सम्मिलित हुए। समिति के संयोजक लोकेश गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन संपूर्ण हिंदू समाज के जागरण व सामाजिक समरसता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सभी के सहयोग से आयोजित किया गया है। हिंदू सम्मेलन में सियाराम बगीची के वेदांती जी महाराज द्वारा हिंदू समाज को जागृत करने हेतु प्रवचन किए गए। समारोह में मुख्य वक्ता संघ के वरिष्ठ प्रचारक मनोज कुमार द्वारा कुटुंब प्रबोधन,पर्यावरण संरक्षण, स्व का जागरण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसताआदि विषयों पर उद्बोधन दिया गया।

सेवानिवृत्ति पर समाजसेवी नगेन्द्र ने दी शुभकामनाएँ

जयपुर @ जागरूक जनता। विद्युत उत्पादन निगम से 31 जनवरी को 33 वर्ष की गोरवमय सेवाएं पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर अशोक कुमार शर्मा अकाउंट्स ऑफीसर लेखा अधिकारी को समाज सेवी नगेन्द्र वशिष्ठ के निर्देशन में सिरसी रोड स्थित पाल वाले हनुमान मंदिर में प्रसादी कार्यक्रम में प्रेम नारायण तिवाड़ी, भवानी शंकर शर्मा ने शुभकामनाएं दी। इस दौरान अंजलि तिवाड़ी, हिमांशु वशिष्ठ भी उपस्थित थे।

उमंग-उत्साह से मनाया वार्षिकोत्सव

जयपुर @ जागरूक जनता। जयपुरिया विद्यालय, जेएलएन मार्ग में वार्षिक उत्सव' Harmony-मूल्यों की स्वर लहरी ' बड़े ही उत्साह, उल्लास एवं सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेन्द्र सिंह राठौड़ रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ– नृत्य, संगीत, नाट्य एवं समूह गायन – के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों एवं समकालीन विषयों की सुंदर झलक देखने को मिली। विद्यालय के प्रधानाचार्या रेणु शर्मा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई।

कृति को नगद राशि व मेडल से किया सम्मानित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 76वां वार्षिक समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि मान्य अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री क़ानून एवं न्याय की अध्यक्षता मे आयोजित किया गया। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंट्स आफ इंडिया के फाउंडेशन, इंटरमीडियट, फ़ाइनल के राष्ट्रीय मेरिट को समान की श्रेणी मे, अहमदाबाद से कृति शर्मा को चार्टेंड अकाउंट को इंटरमीडिएट मे सेकंड रैंक आने के उपलक्ष में 23000 रूपये चेक एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है की कृति शर्मा मूल राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। गौरतलब है कि राजधानी के प्रमुख समाजसेवी नगेन्द्र वशिष्ठ की दोहिति है।

काव्यम् का सीजन-4 काव्यांगन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन बिड़ला सभागार में 22 को

जयपुर @ जागरूक जनता। कला, संस्कृति और साहित्य की संस्था काव्यम् के सीजन-4 काव्यांगन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के नामी कवि-कवयित्री हास्य, श्रृंगार और वीर रस की रचनाओं से शहर के दानिशमंद श्रोताओं को गुदगुदाएंगे और रोमांचित करेंगे। प्रणेता राजेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में 22 फरवरी को शाम 5.45 बजे यहां स्टैच्यू सर्किल स्थित बिड़ला सभागार में होगा। इस बार लाफ्टर चैंपियन और स्टार प्लस व सोनी टीवी फेम हास्य-व्यंग्य के कवि प्रताप फौजदार (आगरा), सब टीवी के वाह - वाह फेम हास्य-व्यंग्य के कवि राजेश अग्रवाल (दिल्ली), सब टीवी के वाह- वाह फेम हास्य-व्यंग्य के कवि हरीश हिन्दुस्तानी, नवलगढ़ (शेखावाटी मारवाड़ी), सब टीवी के वाह- वाह फेम वीर रस के कवि अशोक चारण (जयपुर), सब टीवी के वाह- वाह फेम हास्य-व्यंग्य के कवि हेमन्त पाण्डेय (कानपुर) और सब टीवी के वाह- वाह फेम श्रृंगार रस की कवयित्री मोनिका देहलवी(दिल्ली) अपनी सरल,सहज काव्य रचनाओं से शहर की आबोहवा में हंसी, उल्लास और जोश का काव्य रस घोलेंगे।

दीक्षित ऋषि विजडम ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित

जयपुर @ जागरूक जनता। सेलिब्रिटी और टेरो रीडर आयुषमा दीक्षित को दिल्ली स्थित ज्योतिष एकीकृत अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय वैदिक ज्योतिष-वास्तु और संबद्ध विज्ञान पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान "ऋषि विजडम ग्लोबल अवार्ड" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके संस्थापक और अध्यक्ष दिव्याचार्य राकेश डागर और एआईएफएएस के अध्यक्ष डॉ. अरुण बंसल, सेलिब्रिटी ज्योतिषी जी.डी.वशिष्ठ द्वारा किया गया। आयुषमा ने टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आध्यात्मिकता के जुड़ाव पर अपना भाषण दिया।

केवी विशेषज्ञ इंजीनियर शर्मा सटीक भविष्यवाणियों के लिए सम्मानित

जयपुर @ जागरूक जनता। केपी विशेषज्ञ इंजीनियर कुलदीप शर्मा ने जन्म समय सुधार के लिए उपचंद्र संबंध सिद्धांत पर अपना भाषण दिया और कुंडली में जन्म समय सुधार तथा जातक की कुंडली के लिए सटीक भविष्यवाणियां करने के तरीके बताए। उन्हें दिल्ली स्थित ज्योतिष एकीकृत अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय वैदिक ज्योतिष-वास्तु और संबद्ध विज्ञान पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान "ऋषि विजडम ग्लोबल अवार्ड" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके संस्थापक और अध्यक्ष दिव्याचार्य राकेश डागर और एआईएफएएस के अध्यक्ष डॉ. अरुण बंसल, सेलिब्रिटी ज्योतिषी जी.डी.वशिष्ठ द्वारा किया गया।

अभिनव वर्मा बने पावरग्रिड राजस्थान परियोजना के कार्यपालक निदेशक

जयपुर @ जागरूक जनता। अभिनव वर्मा ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना के कार्यपालक निदेशक (ईडी) का पदभार संभाला। विद्युत क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाले वर्मा को इंजीनियरिंग, निर्माण, परियोजना प्रबंधन, एसेट मैनेजमेंट तथा एचवीडीसी तकनीक में विशेष दक्षता प्राप्त है। उन्होंने पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय में कॉर्पोरेट प्लानिंग एवं स्ट्रैटेजी विभाग में अपनी सेवाएँ प्रदान की थी। साथ ही उनके नेतृत्व में राजस्थान की प्रमुख ट्रांसमिशन विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं, जो देश के सतत विकास लक्ष्यों एवं ऊर्जा विकास को मजबूती प्रदान कर रही हैं।

हिंदू सम्मेलन में दिखा भक्ति संस्कृति राष्ट्रभाव का अद्भुत संगम

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। देवनगर स्थित सामुदायिक केंद्र में वसुंधरा नगर बस्ती और सुभाष नगर बस्ती के ओर से आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन श्रद्धा, उत्साह और एकता के भाव के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में हजारों की संख्या में हिंदू भाई बहिनों ने भाग लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। विभिन्न मंदिरों से निकली कलश यात्रा सामुदायिक केंद्र पहुंची, जिसमें हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से हुई। सम्मेलन में संतों के प्रवचन हुए तथा श्रद्धालुओं को उनके आशीर्वचन प्राप्त हुए। संतों के विचारों ने समाज को संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान राधा-कृष्ण की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। साथ ही 1100 दीपकों से भव्य आरती का आयोजन किया गया, जो श्रद्धा और आस्था का अनुपम दृश्य बना। इसके अलावा अखंड भारत का भव्य नक्शा तैयार कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया।

जीवन सुरक्षा एवं पर्यावरण रक्षा संस्था

डॉ. मोनिका समेत 101 महिलाएं अहिल्याबाई होल्कर प्रेरक मातृ शक्ति अवार्ड से अलंकृत

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। जीवन सुरक्षा एवं पर्यावरण रक्षा संस्था के तत्वावधान में एसकेआईटी कॉलेज सभागार जगतपुरा जयपुर पर बेटी सम्मान महोत्सव का आयोजन हुआ जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में शानदार सफलता अर्जित करने वाली 101 महिलाओं को अहिल्याबाई होल्कर प्रेरक मातृशक्ति अवार्ड से नवाजा गया।

संस्था अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा एवं संयोजक मोहनलाल शर्मा ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि नव चयनित आर ए एस अधिकारी अंजू शर्मा रही तथा अति विशिष्ट अतिथि समाजसेवी रामजीलाल शर्मा कपिल जैन रहे। समारोह में संघर्षशील मातृशक्ति ने मंच से अपनी संघर्ष की कहानी साझा की। समारोह में जयपुर जिले के साथ ही सीकर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, चूरू, नई दिल्ली से मातृशक्ति ने भागीदारी की। समारोह का मंच संचालन अनुष्का शर्मा एवं कोमल सुथार ने किया। इस अवसर पर 101 मातृशक्ति का अहिल्याबाई होल्कर प्रेरक मातृशक्ति अवार्ड से अभिनंदन करते हुए संस्था का दुपट्टा शॉल स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भेंट किया गया। महिला सशक्तिकरण की विषय पर विचार व्यक्त किए गए एवं कालिका पैट्रोलिंग यूनिट ने बालिकाओं को आत्म रक्षा के गुर सिखाएं गये। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि मातृशक्ति समाज की मुख्य स्तंभ है। प्रकृति संवर्धन में मातृशक्ति का सदैव अनुकरणीय योगदान रहा है। इस अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति को प्रतिवर्ष पेड़ लगाकर उसका संवर्धन करने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर सोहनलाल पारीक, गजानन्द शर्मा, मुकेश मेहता, प्रभु दयाल शर्मा, भगवान सहाय शर्मा, महेश, लखन, मुकेश, डॉ. आशा शर्मा, स्नेहा शर्मा, डॉ.मोनिका शर्मा, अमृता मौर्य, सुनीता, आकांक्षा शर्मा, अशोक शर्मा, बंशीधर शर्मा, युवराज शर्मा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं संस्था कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की।

अगर विरासत में मिली हो संपत्ति...

6 बातें हर वारिस को पता होनी चाहिए

विरासत टैक्स-फ्री ज़रूर है, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी तरह खत्म नहीं होती। सही जानकारी और समय पर कार्रवाई करने से न सिर्फ कई तरह की कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है, बल्कि परिवार को भावनात्मक रूप से भी राहत मिलती है।

किसी अपने को खोना भावनात्मक रूप से बेहद कठिन समय होता है। ऐसे समय में अगर टैक्स, रिटर्न और कानूनी औपचारिकताओं की उलझन सामने आ जाए, तो स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। भारत में भले ही इनहेरिटेंस टैक्स (विरासत कर) नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टैक्स से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मौत के बाद टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम करने होते हैं, जिन्हें सही तरीके से न समझने पर नोटिस, पेनल्टी या कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है। आइए इन्हें समझते हैं।

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

किसी की मौत के बाद विरासत में मिली संपत्ति, निवेश या पैसा भावनात्मक राहत तो देता है, लेकिन टैक्स से जुड़े कई सवाल भी खड़े कर देता है। कौन रिटर्न भरेगा, टैक्स किस पर लगेगा और जिम्मेदारी कहां तक होगी? इन सवालों के साफ जवाब जानना बेहद जरूरी है।

पहले से तैयारी ही सबसे अच्छा रास्ता

अगर पहले से दस्तावेज व्यवस्थित रखें, नॉमिनेशन अपडेट रखें और टैक्स नियमों की बुनियादी समझ रखें, तो मुश्किल समय में फैसले लेना ज्यादा आसान हो जाता है और विरासत में मिली संपत्ति सिर्फ सुकून देती है, सिरदर्द नहीं।

मृत व्यक्ति का IT रिटर्न कौन भरेगा?

1 किसी की मौत की तारीख तक की उसकी आय पर टैक्स देय होता है। यानी जिस वित्त वर्ष में मौत हुई, उस साल की शुरुआत से लेकर मौत की तारीख तक की इनकम का टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है।

यह रिटर्न कानूनी वारिस (Legal Heir) भरता है। IT की धारा 139 के तहत वारिस को 'रिप्रेजेंटेटिव असेसी' माना जाता है। यानी वह मृत व्यक्ति की ओर से टैक्स से जुड़े काम करता है।

लेनी होती है मंजूरी

- वारिस को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। फिर 'Authorised Partners' या 'Register as Legal Heir' विकल्प चुनना होता है।
- मृत व्यक्ति का पैन, डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी वारिस होने का प्रमाण अपलोड करना होता है।
- कुछ मामलो मे इंडेम्निटी बॉन्ड भी देना पड़ता है।
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रिक्वेस्ट सबमिट करें, टैक्स डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद वारिस रिटर्न फाइल कर सकता है।

टैक्स रिफंड किसे मिलेगा?

2 मृत व्यक्ति के नाम पर टैक्स या TDS ज्यादा कटा है, तो रिफंड के लिए रिटर्न फाइल करें। यह रिफंड वारिस को रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में मिलता है। अगर मृत व्यक्ति का बैंक खाता बंद है, तो वारिस को आयकर पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट जोड़कर वैलिडेट करना होता है।

मृतक की आय पर भी टैक्स?

3 हां, लेकिन सीमित जिम्मेदारी के साथ। मौत की तारीख तक की आय टैक्सेबल होती है। हालांकि वारिस को अपनी निजी कमाई या संपत्ति से टैक्स चुकाने की बाध्यता नहीं होती। टैक्स, ब्याज या पेनल्टी की वसूली केवल विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक ही की जा सकती है।

विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स के नियम जानें

संपत्ति	ब्याज / किराया / डिविडेंड पर टैक्स	बिक्री पर टैक्स
लिस्टेड शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड	■ घरेलू स्रोतों से मिलने वाला डिविडेंड 'अन्य स्रोत से आय' में जोड़ा जाता है। स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगता है। TDS कटता है।	■ लंबी अवधि पूंजीगत लाभ (LTCG): 1.25 लाख से ऊपर के लाभ पर 12.5% टैक्स। शॉर्ट टर्म पूंजीगत लाभ (STCG): 20% टैक्स।
प्रॉपर्टी (घर / जमीन)	■ किराया 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' में जोड़ा जाता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है।, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन के ब्याज की छूट (यदि लागू हो)।	■ 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी प्रॉपर्टी पर LTCG टैक्स 12.5% बिना इंडेक्सेशन लगेगा। इससे पहले खरीदी प्रॉपर्टी पर 12.5% बिना इंडेक्सेशन या 20% इंडेक्सेशन के साथ विकल्प है। STCG पर टैक्स स्लैब रेट से लगता है।
बैंक डिपॉजिट और (FD)	■ ब्याज 'अन्य स्रोत से आय' में जोड़ा जाता है। स्लैब रेट के अनुसार टैक्स। TDS कटता है।	■ लागू नही (NA)
लाइफ इंश्योरेंस	■ लागू नही (NA)	■ डेथ बेनिफिट आमतौर पर टैक्स-फ्री होता है।
क्रिप्टो	■ लागू नही (NA)	■ मुनाफे पर 30% टैक्स, साथ मे सरचार्ज और सेस।
सोना-जूलरी	■ लागू नही (NA)	■ LTCG पर 12.5% (2 साल बाद), STCG स्लैब पर।

ऐसी संपत्ति से आय पर टैक्स कैसे लगेगा?

भारत में विरासत में संपत्ति मिलना टैक्स-फ्री होता है।

4 यानी घर, जमीन, शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी या नकद राशि मिलने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही उस संपत्ति से आगे चलकर कोई आय होती है, वह टैक्स के दायरे में आ जाती है।

कुछ उदाहरण समझिए

कैपिटल गेंस: आपने विरासत में मिली प्रॉपर्टी या शेयर बाद में बेच दिए, तो उससे मुनाफे पर कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। खरीद की कीमत वही होगी, जिस पर मृत व्यक्ति ने वह संपत्ति खरीदी थी, और होल्डिंग पीरियड भी उसी तारीख से गिना जाएगा।

ब्याज और डिविडेंड: एफडी, सेविंग अकाउंट या बॉन्ड से मृत्यु के बाद जो ब्याज मिलेगा, वह वारिस की इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। इसी तरह, शेयर या म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा।

घर का किराया: अगर विरासत में मिला घर किराए पर है, तो मौत के बाद मिलने वाला किराया वारिस की आय माना जाएगा। अगर एक से ज्यादा वारिस है, तो किराया उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से टैक्सेबल होगा। वारिस को सेक्शन 24 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन के ब्याज की छूट भी मिल सकती है, बशर्ते शर्तें पूरी हो।

क्या कर्ज़ भी विरासत में मिलता है?

कर्ज अपने आप वारिस की निजी जिम्मेदारी नहीं बनता।

5 आमतौर पर लोन की वसूली मृत व्यक्ति की संपत्ति या गिरवी रखी गई संपत्ति बेचकर की जाती है। कर्ज संपत्ति से ज्यादा है, तो वारिस को जेब से पैसा देने की मजबूरी नहीं होती। वारिस चाहें तो विरासत लेने से इनकार भी कर सकते हैं। हालांकि, अगर वारिस लोन का गारंटर या को-बॉरोअर रहा है, तो जिम्मेदारी बन सकती है। PF और लाइफ इंश्योरेंस आम तौर पर कर्ज वसूली से सुरक्षित रहते हैं।

क्या लाइफ इंश्योरेंस का पैसा टैक्सेबल होता है?

ज्यादातर मामलों में लाइफ इंश्योरेंस का डेथ बेनिफिट टैक्स-फ्री होता है और आयकर कानून की धारा 10(10D) के तहत इसे छूट मिलती है।

6 हालांकि कुछ अपवाद हैं। अगर बीमा राशि किस्तों में मिलती है या भुगतान में देरी के कारण उस पर ब्याज जुड़ता है, तो ब्याज वाली रकम टैक्सेबल हो सकती है। अगर पॉलिसी की राशि एस्टेट में जाती है, तो टैक्स ट्रीटमेंट बदल सकता है। रकम टैक्स-फ्री हो, तो भी उसे इनकम टैक्स रिटर्न में Exempt Income के रूप में दिखाना होता है। पति, पत्नी, माता-पिता और बच्चे बेनिफिशियल नॉमिनी माने जाते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में नॉमिनी केवल ट्रस्टी के रूप में होता है।

आज के बजट में व्यापारियों और उद्योगों को मिली राहत

» **जागरूक जनता** @ केंद्र सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट में व्यापारियों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हितों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए आसान ऋण, क्रेडिट गारंटी और वित्तीय सहयोग के प्रावधान किए गए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को कार्यशील पूंजी की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से उद्योगों में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

- प्रवीण सुथार, फोर्टी, राजस्थान ब्रांचेज

2026-27 का बजट विकास में दूरगामी परिणाम वाला

» **जागरूक जनता** @आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टीडीएस व टीसीएस का प्रतिशत कम किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिये उत्पादकता पर जोर दिया जायेगा। पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण होगा। वस्त्र उद्योग सेक्टर में कई रिफोर्म किये जायेंगे। रेयर अर्थ मेटल के लिये नयी योजना लायी जायेगी। एमएसएमई विकास में त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। 11 नये जलमार्ग बनाये जायेंगे। कैंसर तथा डायबिटिज की दवा जिनकी संख्या 17 होगी, रियायती दर पर उपलबध करवायी जायेगी। तीर्थस्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये छोटे शहरों में भी तीर्थस्थल विकसति किये जायेंगे।

बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, चेयरमेन, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ

टियर 2 व टियर 3 के शहरों को ज्यादा फायदा मिलेगा

» **जागरूक जनता** @ केंद्रीय बजट 2026-27 में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सरकार ने दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निवेश से खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाले कदमों से इस सेक्टर को अहम लाभ मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। कुल मिलाकर, बजट 2026 रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग-टर्म में सकारात्मक है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के दृष्टिकोण से। हालांकि, तात्कालिक टैक्स राहत की कमी के कारण शॉर्ट-टर्म में सीमित लाभ देखने को मिल सकता है। इन सभी उपरोक्त कर्ण को देखते हुए जयपुर सहित पूरे राजस्थान में रियल एस्टेट में मांग तथा रेट में व्यापक वृद्धि के आसार हैं।

नवीन भूटानी, राजस्थान रियल्टर्स, जयपुर

केंद्रीय बजट विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

» **जागरूक जनता** @ केंद्रीय बजट 2026 राष्ट्र के समग्र विकास, आर्थिक स्थिरता एवं सामाजिक संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल है। यह बजट उद्योग, व्यापार, शिक्षा, रोजगार एवं मध्यम वर्ग को सशक्त करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को और मजबूती प्रदान करता है। सरकार द्वारा विकास, समावेशन और नवाचार पर दिया गया विशेष बल, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा तथा समाज के सभी वर्गों में विश्वास और आशा का संचार करेगा। यह बजट एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राजकुमार मित्तल, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा वैवाहिक परिचय प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कुमार मित्तल ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वैवाहिक परिचय प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। इस नवगठित प्रकोष्ठ की अध्यक्षता (अतिरिक्त प्रभार) अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार मित्तल को सौंपी गई है। 17 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाज के विभिन्न प्रांतों से सक्रिय, अनुभवी एवं समर्पित पदाधिकारियों को दायित्व प्रदान किया गया है। इसमें उमा बंसल, वसुंधरा मित्तल एवं श्रवण कुमार को राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है। झारखण्ड : संजय कथूरिया एवं श्रीमती माधुरी गोयल (सिमडेगा), मध्य प्रदेश : रामेश्वर दयाल सिंघला, महाराष्ट्र : शीतल केडिया, पश्चिम बंगाल : संतोष अग्रवाल, उत्तर प्रदेश : रश्मि अग्रवाल, दिल्ली : कृष्णा कुमार बंसल एवं सुनीता अग्रवाल, पंजाब : अंजू गुप्ता, उत्तराखंड : कविश मित्तल, ओडिशा : बबिता क्लानोरिया, छत्तीसगढ़ : डॉ. नीरज अग्रवाल, राजस्थान : अशोक अग्रवाल को प्रांतीय प्रभार सौंपा गया है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कुमार मित्तल ने कहा कि वैवाहिक परिचय प्रकोष्ठ का उद्देश्य अग्रवाल समाज के अविवाहित युवक-युवतियों के लिए उपयुक्त वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सहयोग करना है। यह प्रकोष्ठ संस्था स्तर पर सुनियोजित, पारदर्शी एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप प्रयास करेगा।

GST नोटिस से बचना है? रोज़ की अकाउंटिंग में ये चूक न करें

छोटा कारोबार, बड़ी उलझन

नंदकिशोर वर्मा
jagrukjanta.net

भारत के छोटे कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन GST और टैक्स से जुड़ी उलझनें उनकी रफ्तार थाम लेती हैं। रोजमर्रा के कामकाज में छोटी-छोटी चूक बड़ी परेशानी बन जाती है लेकिन सही तैयारी और स्ट्रैटजी से इन्हें रोका जा सकता है।

(लेखक टैली सॉल्यूशंस में सेल्स डायरेक्टर है।)

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मझोले कारोबार यानी MSMEs हैं। दुकान से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक, लाखों छोटे कारोबारी देश की ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद GST और टैक्स से जुड़ी जटिलताएं आज भी ज्यादातर कारोबारियों के लिए तनाव और उलझन का बड़ा कारण बनी हुई हैं। यह स्थिति तब है, जब डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ्टवेयर पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध हैं।

असल समस्या न तो नीयत की कमी है और न ही नियम मानने से बचने की कोशिश। ज्यादातर छोटे कारोबारी टैक्स नियमों का पालन करना चाहते हैं। परेशानी वहां शुरू होती है, जहां रोजमर्रा के बिजनेस के साथ अकाउंटिंग और टैक्स मैनेजमेंट को संभालना मुश्किल हो जाता है।

रोज़मर्रा के काम में उलझकर पीछे छूट जाता है GST

एक छोटे कारोबारी को रोजाना कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ग्राहकों से बातचीत, सप्लायर्स से माल मंगाना, स्टॉक का हिसाब रखना, पेमेंट वसूली, कर्मचारियों की देखरेख और कारोबार बढ़ाने की योजना बनाना, ये सब काम एक साथ चलते हैं। ऐसे में GST कंप्लायंस अक्सर प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे चला जाता है। ज्यादातर कारोबारी GST से जुड़े काम को तब तक टालते हैं, जब तक रिटर्न भरने की तारीख नजदीक न आ जाए या फिर टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस न मिल जाए। तब तक रोजमर्रा की अकाउंटिंग में हुई छोटी-छोटी चूक बड़ी समस्या बन चुकी होती हैं। इन गलतियों को सुधारने में अतिरिक्त समय, पैसा लगता है और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, जो कारोबार की रफ्तार को धीमा कर देता है।

गलतियां कहां से शुरू होती हैं?

अक्सर लोग मानते हैं कि GST की दिक्कतें रिटर्न भरते समय होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर समस्याएं ट्रांजैक्शन के स्तर पर, यानी रोज के अकाउंटिंग काम से ही शुरू हो जाती हैं।

कुछ आम गलतियां ऐसी होती हैं

- दिन-प्रतिदिन अकाउंटिंग में गलत डेटा एंट्री हो जाना, जैसे इनवॉइस अमाउंट या टैक्स वैल्यू गलत डाल देना।
- B2B और B2C सेल्स को गलत कैटिगरी में दर्ज कर देना।
- माल या सर्विस पर गलत GST रेट चुन लेना।
- इनवॉइस में जरूरी जानकारी जैसे GSTIN, HSN या SAC कोड, या सप्लाई की जगह (Place of Supply) गलत या अधूरी होना।
- कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई का सही तरीके से ट्रीटमेंट न करना।
- ई-वे बिल बनाते समय गलत या अधूरी जानकारी भर देना।
- सेल्स, परचेज और GST रिटर्न का समय पर मिलान नही करना।

अलग-अलग देखने पर ये गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ बड़ी समस्या बन जाती हैं। जब सेल्स और परचेज़ डेटा GST रिटर्न से मेल नहीं खाता, तो ITC अटक जाता है, कैश फ्लो प्रभावित होता है और टैक्स अधिकारियों की जांच बढ़ती है। कई MSME को इन दिक्कतों का पता नोटिस मिलने पर चलता है, तब तक सुधार करना तनावपूर्ण हो जाता है।

छोटी चूक कैसे बन जाती है बड़ी दुश्वारी?

- GST सिस्टम में आज की छोटी गलती कई हफ्तों या महीनों बाद सामने आ सकती है। अगर किसी इनवॉइस में आज GSTIN या सही डिटेल नही डाली गई, तो आगे चलकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC अटक सकता है।
- गलत कैटिगरी में की गई सप्लाई से या तो टैक्स कम भर दिया जाता है या ज्यादा, दोनों ही स्थितियां परेशान करती है। ई-वे बिल की गलती से गाड़ी रुक सकती है, डिलीवरी लेट हो सकती है और बिजनेस की साख पर असर पड़ता है।
- ज्यादातर MSMEs के पास अलग से टैक्स या कंप्लायंस टीम नही होती। समस्या का पता तब चलता है, जब या तो डेडलाइन सिर पर होती है या फिर नोटिस आ चुका होता है। तब सही रणनीति बनाने का मौका नही मिलता है।

सिर्फ नोटिस से बचना GST का मकसद नही

कई कारोबारी GST कंप्लायंस को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी मानते है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए, तो यह बिजनेस के लिए फायदे का सौदा भी बन सकता है।

- सही GST मैनेजमेंट से कैश फ्लो पर बेहतर कंट्रोल मिलता है, क्योंकि ITC समय पर और सही मात्रा में क्लेम हो पाता है।
- टैक्स की सटीक गणना से मुनाफे की स्थिति साफ रहती है और फैसले आसान होते है।
- साफ अकाउंट्स से बैंक और लेंडर्स का भरोसा बढ़ता है।
- सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है।

टेक्नॉलजी का सही इस्तेमाल

आज टेक्नॉलजी GST कंप्लायंस को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है, बशर्ते उसका मकसद सिर्फ रिटर्न बनाना नही, बल्कि रोजमर्रा की गलतियों को रोकना हो। अच्छा सॉफ्टवेयर नियमो के साथ अपडेट रहता है, बैंक, GSTN और बिजनेस डेटा को जोड़ता है और अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग और रिकॉन्सिलिएशन को सरल बनाता है। इससे GST कंप्लायंस बोझ नहीं, रोज के काम का हिस्सा बन जाता है।

नियमों से अपडेट रहना ज़रूरी

- **लगातार बदलाव:** GST सिस्टम बदल रहा है। GST 2.0 से कंप्लायंस आसान होगा, लेकिन छोटे कारोबारियो के लिए नियमो के साथ अपडेट रहना और शुरुआती गलतियो से बचना ज्यादा जरूरी हो गया है।
- **रोकथाम ज़रूरी:** GST कंप्लायंस का भविष्य गलतियां सुधारने मे नही, बल्कि उन्हे पहले ही रोकने मे है। बेहतर प्रक्रियाए, बुनियादी समझ और टैलीप्राइम जैसे एडैप्टिव सॉफ्टवेयर इसमें मददगार साबित होंगे।
- **नया नजरिया रखें:** GST कंप्लायंस डर का कारण नही होना चाहिए। सही टेक्नॉलजी से कंप्लायंस रोजमर्रा का हिस्सा बनता है और कारोबार को भरोसे, नियंत्रण और लंबे समय की ग्रोथ की मजबूत नींव देता है।

भक्ति, सेवा, सुरक्षा एवं स्थायी सुविधाओं के सशक्त प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरण

माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पर जसोलधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

बालोतरा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पावन एवं विशेष तिथि त्रयोदशी के अवसर पर श्रीराणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल में श्रद्धालुओं की अत्यधिक एवं अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। प्रातः वेला से ही श्रद्धालु सुव्यवस्थित कतारों में श्री राणीसा भटियाणीसा के दर्शन हेतु लगने लगे तथा यह क्रम पूरे दिवस श्रद्धा, संयम एवं अनुशासन के साथ निरंतर चलता रहा। मां जसोल के असंख्य भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प के साथ संस्थान अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल द्वारा हवन में विशेष आहुतियां अर्पित की गईं। इस अवसर पर मां जसोल से सुख-समृद्धि, शांति, सामाजिक समरसता एवं समस्त श्रद्धालु परिवारों के कल्याण की मंगल कामना की गई। हवन कार्यक्रम श्रद्धा एवं वैदिक मंत्रोच्चार के वातावरण में संपन्न हुआ।

इस पावन तिथि पर श्रद्धालुओं ने श्री राणीसा भटियाणीसा के पावन दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक मंगल, संतान सुख एवं सामाजिक कल्याण की मंगलकामनाएं कीं। साथ ही श्रद्धालुओं ने श्री राणीसा भटियाणीसा, श्री बायोसा, श्री सवाई सिंह जी, श्री लाल बन्ना सा, श्री खेतलाजी एवं श्री काला-गौरा भैरूजी के मंदिरों में विधिवत पूजा-अर्चना कर दर्शन लाभ प्राप्त किया। वृद्धजन, महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग तथा नवविवाहित जोड़ों ने विशेष भाव-भक्ति के साथ मां जसोल के चरणों में नतमस्तक होकर दर्शन किए। विशेष तिथि त्रयोदशी के अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिसर भक्ति, श्रद्धा एवं अनुशासन के वातावरण से ओत-प्रोत रहा। श्रद्धालुओं को सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संस्थान प्रशासन द्वारा व्यापक एवं बहु-स्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। मंदिर परिसर में सुव्यवस्थित दर्शन पंक्ति संचालन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, छायादार विश्राम स्थल, बैठने की समुचित सुविधा, नियमित साफ-सफाई, सूचना व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से अनाउंसमेंट, मार्गदर्शन केंद्र तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं हेतु विशेष सहयोग व्यवस्था की गई। प्रवेश एवं निकास द्वारों पर नियंत्रित प्रबंधन के माध्यम से भीड़ नियंत्रण को प्रभावी ढंग से संचालित किया गया।

आईसीएआर के पश्चिम क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता-2025

सीएमडब्ल्यूआरआई ने फाइनल में जीता गोल्ड

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

टोंक। भाकृअनुप-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसन्धान संस्थान अविकानगर मे आयोजित हो रहे "आईसीएआर के पश्चिम क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता-2025" में CSWRI अविकानगर की फुटबॉल टीम कप्तान डॉ राजीव कुमार के लीडरशिप मे IVRI बेरली की टीम को पेनल्टी शूटआउट गोल मे 3-0 से हराकर फाइनल मुकाबला जीतकर गोल्ड पर कब्जा किया। अविकानगर की फुटबॉल टीम मे किकर डॉ विनोद कदम, सीताराम माली, सुदाशु शर्मा एवं गोलकीपर डॉ चेतन पाटिल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अविकानगर टीम इस जोन मे पहली बार ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। निदेशक डॉ अरुण कुमार तोमर ने अपने फुटबॉल टीम कप्तान डॉ राजीव कुमार को एवं सभी प्लेयर को दी हार्दिक बधाई के साथ अपनी सुभकामनाये दी। लेडीज क्लब प्रेजिडेंट पूनम तोमर, डॉ नेहा कुमारी तोमर ने भी अपनी सभी क्लब सदस्यों के साथ अविकानगर टीम का जोरदार उत्साहवर्धन किया। अविकानगर ने कोई गोल नहीं करने दिया एवं फाइनल पेनल्टी मे जोरदार बचाव के साथ विजय प्राप्त की। अविकानगर के मीडिया प्रभारी अमरसिंह मीना ने जानकारी दी।

आदिवासियों का महातीर्थ बेणेश्वर धाम उमड़ा रहा भजन-भक्ति का ज्वार

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

बांसवाड़ा। आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर महामेला इन पिछले कई दिन से निरन्तर जारी है। यह कृष्ण पक्षीय पंचमी तिथि 6 फरवरी शुक्रवार को हरि मन्दिर पर ध्वजावतरण के साथ सम्पन्न होगा। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एवं अछूतोद्धारक संत तथा लीलावतार के रूप में लाखों-करोड़ों भक्तों में पूज्य रहे मावजी इस क्षेत्र की धड़कन में समाहित हैं।

आज भी श्रीकृष्ण के अंशावतार की तरह मावजी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा के भाव विद्यमान हैं। यह बेणेश्वर धाम मावजी की लीलास्थली रहा है। हिन्दुस्तान में वनवासियों के इस सबसे बड़े मेले को 'आदिवासियों के कुम्भ' की संज्ञा दी गई है। वनवासी संस्कृति एवं समाज के विभिन्न आयामों का जीवन्त दिग्दर्शन कराने वाला यह मेला आंचलिक संस्कृति का प्रतिदर्श है, जिसे देखकर वागड़ अंचल के सामाजिक एवं परिवेशीय परिवर्तनों का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। ख़ासकर इस मेले में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से अलग-अलग सम्प्रदायों, मतों, पंथों, अखाड़ों, धूणियों एवं आश्रमों-मठों से जो महंत, भगत एवं समाज सुधारक हिस्सा ले रहे हैं। उनके द्वारा दिन-रात प्रवाहित भक्ति लहरियां वातावरण को आध्यात्मिक सुरभि से महका देती है और समूचे बेणेश्वर में समकालीन भक्ति धाराओं के कई-कई चित्र अच्छी तरह उभर कर सामने आते हैं।

विराट हिन्दू सम्मेलन ने समाज में एकता, समरसता और सांस्कृतिक जागरण का दिया संदेश

जात-पात त्याग कर एक हिंदू पहचान रखे-मोनी बाबा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

भुसावर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भुसावर कस्बे के सैरकी जलाशय के सामने जिन्दल फार्म हाउस पर विराट हिन्दू सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ पारंपरिक कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति, श्रद्धालु और धर्मप्रेमी नागरिक शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान सनातन संस्कृति के जयघोष से सम्पूर्ण क्षेत्र भक्तिमय हो गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासींन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर सामूहिक हनुमान चालीसा से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोभानंद महाराज उर्फ मौनी बाबा उलूपुरा वाले रहे।धर्मजारण मंच के जयपुर प्रांत संयोजक अमरसिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दी। उन्होंने हिन्दू एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि हिन्दू एक होगा तो समस्त भारत एक होगा। कोई भारत पर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। मातृशक्ति के रूप में ब्रह्मकुमारी गीता बहन ने अपना उद्बोधन आध्यात्म पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौनी बाबा ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने उद्बोधन में जात पात त्यागकर केवल एक पहचान हिन्दू रखना ही हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ किया गया।

बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में दर्ज की 71% बढ़ी शुद्ध लाभ

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

चित्तौड़गढ़। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में 53 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 71 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कंपनी का समेकित ईबीआईटीडीए 18 प्रतिशत बढ़कर 312 करोड़ रुपये रहा। सीमेंट डिवीजन का ईबीआईटीडीए मार्जिन 14.8 प्रतिशत रहा, जबकि उत्पादन लागत में 4 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, सीमेंट बिक्री मात्रा 6 प्रतिशत घटने से समेकित राजस्व 4 प्रतिशत घटकर 2,178 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने प्रीमियम व मिश्रित सीमेंट की बिक्री पर जोर दिया, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार हुआ और प्रति टन ईबीआईटीडीए 23 प्रतिशत बढ़कर 702 रुपये पहुंच गया। नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग बढ़ाने से बिजली-ईंधन लागत में भी कमी दर्ज की गई। जूट डिवीजन को कच्चे जूट की कमी और कीमतों में वृद्धि के कारण 2.14 करोड़ रुपये की नकदी हानि हुई, हालांकि जूट एवं शॉपिंग बैग से राजस्व 31 प्रतिशत बढ़कर 132 करोड़ रुपये रहा।

ग्राहकों के विश्वास की चिंता करता है अर्बन बैंक- डॉ. सेठिया

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

निंबाहेड़ा। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की निंबाहेड़ा शाखा द्वारा आयोजित रजत जयंती सक्रांति महोत्सव बैंक अध्यक्ष डा आई एम सेठिया की अध्यक्षता व पूर्व विधायक अशोक नवलखा, निदेशक बाल किशन धूत, हेमंत शर्मा,बाबर मल मीना, कल्याणी दीक्षित, हरीश आहूजा, प्रमुख उद्यमी सुशील चौधरी, प्रियंक नरेडी, भजन जिज्ञासु, पारस वीरवाल, ललित शारदा, सिद्धराज सिंघवी प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी के आथित्य में झूलेलाल भवन पर संपन्न हुआ। बैंक अध्यक्ष डा सेठिया ने अध्यक्षीय उद्बोधन में अर्बन बैंक की स्थापना व कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की प्रतिस्पर्धा के दौर में सीमित साधनों के बावजूद बैंक ने सभी आधुनिक तकनीक माध्यमो को अपना कर विशेषकर युवा ग्राहकों को जोड़ने का प्रयास किया है। डा सेठिया ने कहा की बैंक ने समाज के मध्यम वर्ग के जनविश्वास को प्राथमिकता देते हुए बड़े बैंको के समकक्ष सेवाए देने के साथ ही न्यूनतम ब्याज दर ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने बैंक की स्थापना से लेकर आज तक की प्रगति यात्रा का साक्षी होने के साथ ही ग्राहकों के विश्वास को प्राथमिकता देते हुए बैंक की मजबूती के लिए सराहनीय प्रयास किए है। बैंक की प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी ने स्वागत उद्बोधन व बैंक की विस्तृत परिचयात्मक जानकारी प्रस्तुत की। विशिष्ट अतिथि भजन जिज्ञासु, सिद्ध राज सिंगवी, निदेशक हरिश आहूजा,बाल किशन धूत कल्याणी दीक्षित ने भी बैंक के कार्यक्रलाप की सराहना करते हुए कहा की बैंक जिले के मध्यम वर्ग को जोड़कर उनको आर्थिक संबल प्रदान करने का सराहनीय काम कर रहा है। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ ही महाप्रबंधक दिनेश खंडेलवाल व जे पी जोशी प्रबंधक मदन विरवाल, तकनीकी प्रबंधक राकेश दशोरा, प्रबंधक प्रशासन राजेश अवस्थी, क्षेत्रीय प्रबंधक दामोदर चेचानी, आरती खानचंदानी, मनोज तंबोली ने मंचासिन अतिथियों का उपरना से अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक दिनेश खंडेलवाल व जे पी जोशी ने किया व आभार शाखा प्रबंधक मदन वीरवाल ने व्यक्त किया ।

कार्यक्रम मे प्रमुख गणमान्य बंधु मोती लाल आहूजा, सिद्धराज गोखरू प्रदीप मोदी, अनिल धूत सीए रोहित नागोरी, भजन लाल ललित शारदा प्रियाक नरेडी सुशील चौधरी पारस वीरवाल रवि कृपलानी प्रियंका चाष्ठा नाना लाल भूतडा किशोर चिमनानी विनोद नागोरी रत्नेश काबरा रामसाहय काबरा सिद्धूराज सिंघवी जगदीश राजोरा पवन छिपा रोहित नागोरी हस्थी मल दुग्गड विजय मारु आदि लोग उपस्थित थे

प्रथम एवं द्वितीय गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई स्थगित

बालोतरा @ जागरूक जनता। निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के मद्देनजर फरवरी माह के प्रथम एवं द्वितीय गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रगति पर है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्तता को दृष्टिगत रखते हुए जन अभियोग निराकरण विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार माह फरवरी 2026 के प्रथम एवं द्वितीय गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई को स्थगित किया गया है।

डॉ गौरव प्रताप सिंह ने पहले प्रयास में की एमसीआई परीक्षा उत्तीर्ण

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

केकड़ी। एडवोकेट बृजेन्द्र प्रताप सिंह के पुत्र डॉ गौरव प्रताप सिंह ने प्रथम प्रयास में एमबीबीएस की राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा फोरेन मेडिकल ग्रेजुएड एग्जामिनेशन पास की। डॉ. गौरव के केकड़ी आगमन पर बार एसोसियेशन केकडी के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड व धनोप माता ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह राणावत व समाज बन्धुओं ने तथा बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत व कार्यकारिणी द्वारा शुभकामानऐं प्रेषित की गई इस दौरान बद्रीविशाल दाधीच, मीठू सिंह राठौड, भंवर सिंह राठौड, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवाकेट रामसिंह राठौड, पवन सिंह भाटी, सूर्यकान्त दाधीच उपस्थित रहे। डॉ गौरव प्रताप सिंह ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व गुरूजनों को दिया और कहा कि मेहनत व परिजनों के आशीर्वाद से मुझे यह सफलता मिली है।

जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी को शत प्रतिशत लाभ मिले - जिला कलक्टर

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

बालोतरा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला कलक्टर मीटिंग हॉल में आयोजन किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुये जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत लाभार्थी को मिले। समस्त संस्थानों का एनक्रास सर्टिफाइड किया जाने के निर्देश दिए गए। समस्त संस्थानों से सीएचओ, एएनएम व आशा के द्वारा सर्वे के दौरान एनीमिक की शत प्रतिशत स्क्रीनिंग हो। कम हीमोग्लोबिन वाले को एफसीएम इंजेक्शन ज्यादा से ज्यादा लगावे। अति जोखिम समूह का टीबी स्क्रीनिंग शत प्रतिशत हो। समस्त चिकित्सा संस्थानों पर जननी सुरक्षा योजना व लाडो प्रोत्साहन योजना के ड्यू केसेज का भुगतान शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए और समस्त संस्थानों पर समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को निर्देशित किया गया कि एमएलसी और पोस्टमार्टम आनलाइन हो कोई भी चिकित्सा अधिकारी आफलाइन नहीं देवें।

प्रत्येक सप्ताह में एक बार समस्त एम्बुलेंस का समय समय पर निरीक्षण हो। जिला कलक्टर यादव ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। टीबी स्पुटम की जांच शत प्रतिशत हो व उनका समय समय पर फोलो अप हो।

घर मंगवाये जागरूक जनता

सदस्यता फार्म

दिनांक .....

जागरूक जनता हिन्दी अखबार एक उद्देश्य, एक मिशन, एक विश्वास के साथ आमजन की समस्याएं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक गलियारा, भौगोलिक दृष्टिकोण को एक-दूसरे से साझा करने के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं तकनीकी जानकारी पहुंचाकर शहरी एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। जागरूक जनता समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों के साथ- अपने पाठकों के बीच उपस्थित रहता है।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 250/- ☐ दो वर्ष रु. 450/- ☐ तीन वर्ष रु. 600/- ☐ पांच वर्ष रु. 1000/-

डाक से नियमित रुप से निम्न पते पर जागरूक जनता भेजने के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर जागरूक जनता के नाम भेज रहा हूं। फोन-पे, पेटीएम-9829329070

नाम / संस्था का नाम .....

पता : .....

.....

फोन ..... पिन कोड

राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम .....

डिमान्ड ड्राफ्ट / मनीऑर्डर क्रमांक (डीडी/एमओ जागरूक जनता के नाम भेजें)

● सदस्यता रजिस्ट्रेशन क्रं. .....रसीद क्रं. .....

दिनांक ..... हस्ताक्षर

सदस्यता हेतु लिखे प्रसार प्रभारी →

जागरूक जनता
सकारात्मक हिन्दी अखबार
बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.) मो.- 9829329070, 9928022718

ग्रीन कम्यूट को अपनाने वाले विद्यार्थियों को टील्स व सीख करेंगे सम्मानित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

भीलवाड़ा। गांधीनगर स्थित टील्स एजुकेशन ने 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक अभिनव पहल की घोषणा की। संस्थान द्वारा घोषित ग्रीन कम्यूट रिवॉर्ड के अंतर्गत अब वे विद्यार्थी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल से संस्थान आएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह पहल टील्स एजुकेशन एवं सीख सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक नकद राशि दी जाएगी। संस्थान निदेशक अभिलाष मोदी एवं अभिषेक कांकरिया ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। कार्यक्रम में ग्रीन कम्यूट रिवॉर्ड का औपचारिक विमोचन किया गया तथा दो विद्यार्थियों को पहला पुरस्कार (नकद राशि) दी गई। विद्यार्थियों एवं सीनियर प्रोफेशनल्स ने इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

ओलावृष्टि से फसल नुकसान की गिरदावरी कर मुआवजा दे सरकार

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विधानसभा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर शीघ्र गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

विधायक आक्या ने पत्र में बताया कि 1 फरवरी की सांयकाल चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत विजयपुर, अमरपुरा, उदपुरा, घटियावली, गिलुण्ड सहित आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की खेतों में खड़ी अफीम व गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही खेतों में काटकर रखी गई सरसों की फसल भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, जिससे उनकी उम्मीदों को गहरा आघात लगा है और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। विधायक आक्या ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से अनुरोध किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं तथा फसल नुकसान का आंकलन कर किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और आगामी फसल की तैयारी कर सकें।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक ज्ञानेन्द्र मिश्रा के लिए जैमन प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी-1-68, रोड नम्बर-14, वीकेआई, जयपुर से मुद्रित एवं प्रशासनिक और विज्ञापन कार्यालय : बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर-302039 से प्रकाशित। फोन : 0141-3587886

ट्रंप का दावा- डील हुई, टैरिफ घटाया

अमेरिका ने कहा- 25 से 18% किया टैरिफ | PM मोदी बोले- शुक्रिया, ये शानदार घोषणा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

अमेरिका और भारत के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते का सोमवार देर रात ऐलान हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिका जवाबी टैरिफ तत्काल प्रभाव से 18% हो जाएगा। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी ट्रंप को धन्यवाद देते हुए इसकी तस्दीक की और इस पर खुशी जताई। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत भी अमेरिका से तेल गैस और कृषि उत्पादों सहित अन्य चीजों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम करेगा और इसे जीरो कर देगा।

डील के ऐलान से पहले ट्रंप ने मोदी से फोन पर बात की

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी ने रूसी तेल खरीदने से इनकार कर दिया है। भारत अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि PM मोदी ने सहमति जताई है कि भारत भारत 500 बिलियन डॉलर के तेल, कृषि उत्पाद, कोयला, टेक्नॉलजी के अलावा और ज्यादा अमेरिकी चीजें खरीदेगा। इससे पहले ट्रंप और पीएम नरेन्द्र मोदी के बीच टेलिफोन पर बात हुई थी। इसकी जानकारी खुद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी। गोर ने सोशल मीडिया पर लिखा था- स्टे ट्यून्ड, यानी देखते रहिए। ऐसे वक्त में जब विदेश मंत्री जयशंकर भी अमेरिका दौरे पर हैं, गोर के संदेश को अहम माना जा रहा है, वो भी तब जब भारत US के साथ ट्रेड डील को लेकर अर्से से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है।

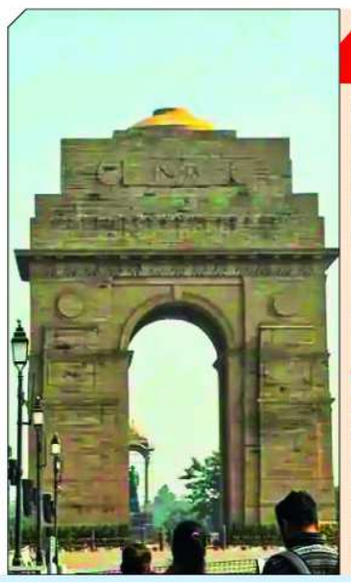

भारत का ट्रायम्फल आर्च (इंडिया गेट) बहुत खूबसूरत है। हमारा वाला इन सबमें सबसे शानदार होगा!
-डॉनल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

अपना गेट बना रहे, ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में अपने नाम से एक गेट बनवाने का प्लान कर रहे है। इस स्मारक को 'आर्क डी ट्रंप' नाम दिया गया है।

PM मोदी से बात के बाद डील का ऐलान

ट्रंप के ऐलान के बाद **PM** मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, उन्हें ट्रंप के साथ बात करके खुशी हुई। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर घटा हुआ 18% टैरिफ लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, जब दो बड़ी इकॉनमी और दुनिया के दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी साथ आती हैं तो कई साझे अवसर और सहयोग, लोगों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हालांकि भारत की ओर से तुरंत इस डील के बारे में आधिकारिक रूप से विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है।

ट्रंप ने किया फोन, पीएम बोले- बात कर खुशी हुई

रूसी तेल पर लगा था 25% और टैरिफ

ट्रंप ने भारत के खिलाफ पहले 25% टैरिफ लगाया था और बाद में पिछले साल अगस्त में रूसी तेल खरीदने के नाम पर और 25% टैरिफ लगा दिया था। इसकी बड़ी चोट भारत के लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड जूलरी जैसे ज्यादा श्रम की जरूरत वाले सेक्टरों से निर्यात पर पड़ रही थी। दिसंबर में अमेरिका को निर्यात सालभर पहले से 1.83% घटकर 688.6 करोड़ डॉलर रहा। अमेरिका का 50% टैरिफ 27 अगस्त को लागू हुआ था। उसके बाद सितंबर से दिसंबर तक अमेरिका को निर्यात 25.6 बिलियन डॉलर का रहा।

रूसी पेनल्टी भी हटी,
ट्रंप ने साफ कर दिया कि रूस से तेल खरीदने पर लग रही 25% की पेनल्टी भी हटा रहे है। इसे मिलाकर अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था।

भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए ये शानदार घोषणा है। जब दो बड़ी इकॉनमी और डेमोक्रेसी साथ आती हैं तो लोगों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। -नरेंद्र मोदी, पीएम

आज से प्रदेशभर में शुरू होगा उचित मूल्य दुकानों के तौलन यंत्रों का सत्यापन

प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर पोस मशीन से लिंक तौलन यंत्रों का अभियान चलाकर होगा सत्यापन

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के लगभग 4.40 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को मिलने वाले राशन का पूरा तौल सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में सभी एनएफएसए लाभार्थियों को उचित तौल के साथ राशन उपलब्ध कराना विभाग का कर्तव्य है ताकि लाभार्थियों के हक़ किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों के

तौलन यंत्रों की सत्यापन कार्यवाही 4 फ़रवरी 2026 से प्रारम्भ की जायेगी। अभियान के तहत राज्य में संचालित उचित मूल्य दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गयी पोस मशीन से लिंक तौलन यंत्रों का विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम 2011 के नियम 27 (2 सी) के तहत सत्यापन किया जाएगा। इस क्रम में आगामी एक माह में जिला रसद अधिकारी ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर सत्यापन कैम्प आयोजित करेंगे जहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी उचित मूल्य दुकानों पर संस्थित तौलन यंत्रों का सत्यापन एवं मुद्रांकन करेंगे। तौलन यंत्र की आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सत्यापन हेतु आवेदन एवं शुल्क संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

गोदारा ने सभी जिला रसद अधिकारियों, विधिक मापविज्ञान अधिकारियों एवं राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तौलन यंत्रों के सत्यापन हेतु मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिये।

सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की एडमिट कार्ड

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड की होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी Admit Card जारी कर दी है। इसे हॉल टिकट भी कहा जाता है. हालांकि इस एडमिट कार्ड को छात्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से जानकारी दी गई है कि रेगुलर स्टूडेंट्स खुद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यह सुविधा सिर्फ स्कूलों के लिए है। सीबीएसई ने कहा है कि सभी स्कूलों को परीक्षा संगम पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद वहां से सभी बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को एडवाइज किया है कि वह अपने एडमिट कार्ड के लिए स्कूल से संपर्क करें। स्कूल के द्वारा उन्हें प्रिंटेड एडमिट कार्ड देगा।

HBOT जीवन रक्षक प्रणाली द्वारा इलाज

ऑक्सीजन (प्राणवायु) ट्रीटमेंट

- मस्तिष्क चोट, पक्षाघात/लकवा
- सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म
- असाध्य घाव/शुगर के घाव
- कैंसर (रेडियो थेरेपी) के साईड इफेक्ट
- अचानक बहरापन (Hearing Loss)
- डाईबेटिक फुट में अम्पुटेशन (पैर कटने) से बचाव

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
98290-17133, 70737-77133
9983317133

डॉ. हिमांशु अग्रवाल M.B.B.S. M.D.

नेशनल हायपरबैरिक रिसर्च सैन्टर
594-B-C, जेम्स कॉलोनी, सैक्टर-3, मंदिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर

Dept. of Hyperbaric Medicine
Fortis Escorts Hospital
JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur

E-mail : hbotjaipur@gmail.com
www.nationalhbot.in

संपादक : ज्ञानेन्द्र मिश्रा मो.-9829329070, फोन : 0141-3587886, ईमेल : jagrukjantanews@gmail.com (सभी मामलों का न्याय क्षेत्र जयपुर) * पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के जिम्मेदार। संपादकीय कार्यालय : 132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान)-302039 समाचार संपादक- चेतेन्द्र कुमार मिश्रा